04 - केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है तापमान का संकट

05 - यूसीसीः संवैधानिक संकल्प से सामाजिक समरसता तक

A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 24 जून, 2026

06 - जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरणः कलेक्टर

07 - सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 262, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

अभी बची है
आस्था
दो पेड़ खड़े-खड़े
बात कर रहे हैं

अभी बची है
आस्था
हर घर उदास
नहीं है

अभी बची है
आस्था
चिड़ियों ने उड़ना
बंद नहीं किया है

अभी बची है
आस्था
आदमी झूठ से
विद्रोह कर रहा है

अभी बची है
आस्था
आदमी ने
पसीना बहाना
बंद नहीं किया है।

-दुर्गाप्रसाद झाला

प्रसंगवश

भारत में विदेशी मीडिया की नई जंग और रणनीतियां

स्टेला डे

क्रेमलिन के सबसे ताकतवर अंतरराष्ट्रीय प्रसारक RT ने पिछले साल भारत में कदम रखा, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। 'बीबीसी' की तरह उसकी कोई पुरानी पहचान नहीं थी। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की तरह उसके पास ऐसा दर्शक वर्ग नहीं था, जो उसके मोदी कवरेज का इंतज़ार कर रहा हो। इसलिए RT ने वही किया जो वह दूसरे देशों में भी करता आया है–उसने भारत की अपनी आवाज़ों को अपनाया।

यूरोप के बड़े हिस्से में प्रतिबंधों का सामना करने और अमेरिका में प्रसारण से बाहर होने के बाद RT India को पिछले दिसंबर नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा काफी प्रचार के साथ लॉन्च किया गया। रूस समर्थित इस नेटवर्क ने जल्द ही अभिनेता अनुपम खेर, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अपने साथ जोड़ा। यह भारतीय पहनावे में क्रेमलिन का टीवी है।

कई दशकों से, विदेशी मीडिया को लेकर भारत का ध्यान इस बात पर रहा है कि पश्चिमी मीडिया देश को कैसे दिखाता है, लेकिन विदेशी मीडिया की एक और तरह की मौजूदगी है, जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता हैः नए खिलाड़ी जो स्थानीय स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं- स्टूडियो, मशहूर हस्तियों, मीडिया पार्टनरशिप और यहां तक कि देश के सबसे बड़े पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ सीधे कंटेंट पाइपलाइन के ज़रिए। कुछ तो दशकों से बिना ज़्यादा चर्चा में आए काम कर रहे हैं। वहीं RT जैसे कुछ दूसरे खिलाड़ी ज़ोर-शोर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।

ये सभी विदेशी प्रसारक भारत की 1.4 अरब आबादी वाले दर्शक बाजार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन उनकी रणनीतियां एक जैसी नहीं हैं। RT का स्वरूप भले ही पूरी तरह भारतीय दिखाई देता हो, लेकिन उसकी प्रस्तुति नहीं। उसका नजरिया पश्चिम-विरोधी, उपनिवेशवाद-विरोधी है और रूस जिस 'ग्लोबल मेजॉरिटी' की बात करता है, उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यही रुख भारत में रूस के दूसरे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म Sputnik में भी दिखाई देता है। दूसरी ओर, भारत में सबसे पुराने विदेशी मीडिया संस्थानों में से एक बीबीसी को नियामकीय जांच और राजनीतिक विवादों के बाद अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना पड़ा है। वहीं जर्मनी का Deutsche Welle (DW) वर्षों से साझेदारियों और डिजिटल सहयोग के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।

सभी एक बात समझते हैं–भारत अब एक ऐसा देश नहीं रह गया है जिस पर सिर्फ रिपोर्टिंग की जाए। इस विशाल बाजार तक पहुंचने के लिए RT ने सबसे आक्रामक रास्ता चुना है। France 24 की वरिष्ठ संपादक लीला जैसिंटो के अनुसार, भारत पर यह नया फोकस पूरी तरह रणनीतिक है। RT इंडिया का लॉन्च रूस के उस बड़े कदम का हिस्सा है जिसे एनालिस्ट 'ग्लोबल साउथ की ओर झुकाव' कहते हैं – यानी पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दर्शकों पर रणनीतिक रूप से ध्यान देना। मॉस्को के साथ पुराने रिश्तों और बड़ी संख्या में दर्शकों की वजह से भारत अगला स्वाभाविक कदम बन गया। फिर भी, RT के भारत ऑपरेशन की खास बात यह नहीं है कि उसने कहां विस्तार किया, बल्कि यह है कि उसने कैसे किया।

एक अहम तरीका है ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना जिन्हें दर्शक पहले से जानते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। चैनल के न्यूज़ ऑपरेशन की कमान रुनझुन शर्मा के पास है, जो एक पत्रकार हैं और जिन्होंने मॉस्को से रिपोर्टिंग करते हुए कई साल बिताए हैं। इसके पॉडकास्ट 'इंडिया, रशिया एंड द वर्ल्ड' में बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, पत्रकार पाल्की शर्मा, 'द हिंदू' की सुहासिनी हैदर और शौर्य डोभाल जैसे लोग शामिल हुए हैं। RT इंडिया के आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से तीन महीने पहले, नेटवर्क ने 'इंपीरियल रिसीट्स' नाम की दस-भागों वाली सीरीज़ शुरू की। इसमें विपक्ष के विद्वान सांसद शामिल थे, जो उपनिवेशवाद-विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। लॉन्च से पहले, RT ने पूरे भारत में ज़बरदस्त विज्ञापन अभियान भी चलाया।

लेकिन, RT चैनल के लॉन्च के समय चले कैंपेन में यह सवाल उठाया गया कि 'पश्चिमी देश आज भी भारत को तीसरी दुनिया का देश क्यों मानते हैं' और RT को 'पश्चिमी-विरोधी नहीं...बल्कि बस पश्चिमी नहीं' बताया गया। दिसंबर में पुतिन की यात्रा के दौरान, RT के लॉन्च के साथ-साथ कई मीडिया समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस बात ने कुछ रिसर्चर्स और प्रेस की आज़ादी के लिए काम करने वाले संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी अफ्रीका में उसने RT, Sputnik Afrique और कई सहयोगी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया, जो स्थानीय लोगों की पहले से मौजूद नाराजगियों को आधार बनाकर अपनी बात फैलाते थे। रूस ने RT और कई सहयोगी नेटवर्कों के जरिए कम से कम 80 दस्तावेज़ित दुष्प्रचार (डिसइन्फॉर्मेशन) अभियान चलाए, जिनका निशाना 22 से अधिक देश थे। France 24 की वरिष्ठ संपादक लीला जैसिंटो मानती हैं कि पश्चिमी अफ्रीका वाला मॉडल भारत में भी अपनाया जा सकता है। अगर RT भारत में रूस की मीडिया रणनीति का टीवी चेहरा है, तो Sputnik उसका न्यूज़रूम है। दोनों संस्थान अलग तरीके से काम करते हैं। Sputnik India की शुरुआत 2022 के अंत में हुई थी। कई वर्षों तक रूसी मीडिया का मुख्य ध्यान पश्चिम पर था, लेकिन 2022 के बाद यह रणनीति बदल गई। ध्यान उन देशों की ओर गया जिन्हें अंतरराष्ट्रीय समाचार कवरेज में ऐतिहासिक रूप से कम जगह मिली है। इस सूची में भारत सबसे ऊपर के देशों में था। Sputnik में भारतीय पत्रकार काम करते हैं, मंत्रालयों से संपर्क रहता है और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अलग-अलग पक्षों की आवाज़ें शामिल की जाती हैं। 1940 में बीबीसी ने भारत में विदेशी प्रसारण की नींव रखी थी। आठ दशकों में उसने विश्वसनीयता और मजबूत ब्रांड पहचान बनाई। लेकिन जहां RT और Sputnik मौजूदा राजनीतिक माहौल का फायदा उठा रहे हैं, वहीं बीबीसी उससे टकरा गया है, जिसके व्यावहारिक असर भी देखने को मिले। बाद में बीबीसी सरकार के निशाने पर आ गया। बीबीसी को भारत में अपने इतिहास के सबसे बड़े पुनर्गठन में से एक करना पड़ा। 2023 के अंत में भारत में तैनात उसके चार वरिष्ठ अधिकारियों–रूपा झा, मुकेश शर्मा, संजॉय मजूमदार और सारा हसन, ने नौकरी छोड़कर Collective Newsroom नाम की एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी बनाई। अब यही कंपनी BBC की छह भारतीय भाषा सेवाओं के लिए कंटेंट तैयार करती है। यह पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी है, जबकि BBC World Service India में BBC की 99 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

अगर भारत के मीडिया परिदृश्य में कोई 'खामोश साझेदार' रहा है, तो वह Deutsche Welle है। उसकी अधिकांश सामग्री युवा और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने वाले दर्शकों के लिए तैयार की जाती है। सफलता लोगों की भागीदारी और पहुंच से मापा जाता है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

15 मौतों के बाद

योगी सरकार एक्शन में

● बड़ी कार्रवाई की है तैयारी, ढहाई जाएगी बिल्डिंग ● यूपी के 20 शहरों के कोचिंग सेंटर्स में छापेमारी ● 33 सेंटर सील, बेटी का शव देखकर मां बेहोश

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ की कोचिंग में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने बिल्डिंग की जांच की। एसआईटी टीम में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। शवों का 7 घंटे तक पोस्टमॉर्टम चला। शव परिजन को सौंप दिए गए। पश्चिम बंगाल की अनामिका (30) का शव देखकर पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंची मां बेहोश हो गईं। जांच में पता चला है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अवैध थी। 2016 में गिराने का आदेश हुआ था। बाद में निरस्त कर दिया गया।

डिंपल बोलीं- हादसे के जिम्मेदारों पर हो सख्त कार्रवाई

लखनऊ कोचिंग कांड पर डिंपल बोलीं- हादसे के जिम्मेदारों पर हो सख्त कार्रवाई लखनऊ अग्निकांड को लेकर सांसद डिम्पल यादव ने कहा- बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें बहुत सारे छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदना है। उन्होंने कहा- सरकार पूरा सहयोग करे, जो बच्चे घायल हैं, उनका सही से इलाज कराए और मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए। घटना की वजह भी पता कराना चाहिए। इस घटना में जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

यूपी के 20 शहरों में कोचिंग-होटलों में छापेमारी

लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, बहराइच और वाराणसी समेत 20 शहरों में पुलिस होटल और कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी कर रही है। अब तक कानपुर में 30, वाराणसी में 2 और नोएडा और मथुरा में 1-1 कोचिंग को सील किया गया है। इसके अलावा बरेली में 2 होटल और मथुरा में 1 होटल को भी सील किया गया है। पुलिस कोचिंग संस्थानों और होटलों में सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। यह देखा जा रहा है कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था है या नहीं, इमरजेंसी गेट मौजूद है या नहीं और आपात स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं या नहीं।

मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले

स्कूल होंगे अपग्रेड, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रहेगी जारी

● राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए 5,960 करोड़ रूपये की योजनाओं को मंजूरी ● मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कल्याणी विवाह सहायता योजना की निरंतरता को मंजूरी, 1,740 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति ● 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल और 300 हाई स्कूल के हायर सेकेण्डरी में उन्नयन को सैद्धांतिक स्वीकृति

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार 960 करोड़ रूपये की योजनाओं सहित कई जनहितैषी कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को गति देते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रखने के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को एक अप्रैल 2026 से पांच सालों तक निरंतर संचालन के लिए 1740 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

शासकीय स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड- इसके साथ ही एमपी कैबिनेट ने शासकीय स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। स्वीकृति अनुसार वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल और 100 हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। आगामी 2 वर्षों 2027-28 एवं 2028-29 में भी इसी प्रकार प्रतिवर्ष 75 माध्यमिक और 100 हाईस्कूलों के उन्नयन पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। साथ ही विद्यालयों के उन्नयन के लिए अनुमानित व्यय राशि 635 करोड़ 24 लाख रुपए के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। विकसित मध्यप्रदेश@2047 के तहत वर्ष 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिला स्तर से मैपिंग अनुसार 315 हाई स्कूल एवं 214 हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सांदीपनि विद्यालयों के कैचमेंट एरिया में विद्यालयों का उन्नयन नहीं किया जाएगा। सांदीपनि विद्यालय के कैचमेंट एरिया में आने वाले विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में होने पर विद्यालय को अन्य आवश्यकता वाले स्थानों पर युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। उन्नत विद्यालय अपने वर्तमान भवन और अन्य शासकीय भवन में संचालित होंगे।

किसानों के हित में लिए फैसला

कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना अंतर्गत किसानों के हित में शर्तों की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार खरीफ और रबी सीजन के लिए पृथक-पृथक देय तिथि (ड्यू डेट) नहीं रखते हुए उसके स्थान पर वार्षिक एकल ऋण सीमा रखी जाएगी। इसमें नगद और वस्तु ऋण की उप-सीमा निर्धारित रहे। योजनान्तर्गत देय तिथि (ड्यू डेट) कृषकों को स्वीकृत वार्षिक एकल लिमिट से प्रथम ऋण आहरण से 12 माह निर्धारित की जाएगी और अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को 1.25 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर लगा था गद्दार का टैग

● स्पीकर के फैसले से बच पाई सोफिया फिरदौस की विधायकी

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा में पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक सोफिया फिरदौस के राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने पर बड़ा बवाल मचा था। कांग्रेस पार्टी ने सोफिया फिरदौस समेत दूसरे विधायकों को क्रॉस वोटिंग पर पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इन पद गद्दारी का आरोप लगा था। इसके बाद कांग्रेस और बीजेडी दोनों सदस्यता खत्म करने के अर्जियां स्पीकर को दी थीं। स्पीकर स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने सोमवार को 11 विधायकों (बीजेडी के आठ और कांग्रेस के तीन) के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सोफिया समेत 11 विधायकों को मिली राहत

ओडिशा विधानसभा स्पीकर के समक्ष ये याचिकाएं 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने के कारण दायर की गई थीं। स्पीकर ने हर विधायक के लिए अलग-अलग आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाओं में सही वेरिफिकेशन और सपोर्टिंग सबूतों की कमी थी। बीजेडी विधायकों में चक्रमणि कन्हार (बालीगुडा), नबा किशोर मल्लिक (जयदेव), सौविक बिस्वाल (चौद्वार-कटक) आदि शामिल थे।

मुंबई पहुंचा मानसून, झमाझम बारिश शुरू

● बिहार-छत्तीसगढ़ के कई इलाके किया कवर ● इसी हफ्ते में एमपी और यूपी में देगा दस्तक

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून 12 दिन की देरी के बाद मंगलवार को मुबंई पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। मानसून के पहुंचते ही शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। इसके बाद 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री होगी। इधर, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। छतरपुर में बिजली गिरने से दो लड़कियां झुलस गईं। इनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं, पंजाब के अमृतसर में आंधी से पेड़ गिरने से बच्चे की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सोमवार दोपहर बाद बारिश हुई। बस्ती में आंधी-बारिश की वजह से पेड़-पोल उखड़ गए। एक पेड़ कार पर गिरा। सड़क पर पोल गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। हैदराबाद में तेज बारिश हुई। कई सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली भी गुल रही। मंगलवार सुबह 5 बजे तक केथीरेड्डीपल्ली में 12.9 सेमी, चंदानगर में 12.7 सेमी और लिंगमपल्ली में 11.7 सेमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने तेलंगाना के जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, मेडक और कामारेड्डी जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को जुलाई तक इंतजार

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को जुलाई तक इंतजार करना होगा। सोमवार तक देश में सामान्य 106 मिमी की तुलना में सिर्फ 60.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यानी अभी तक 43 फीसदी कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई शहरों में बुधवार को पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 43.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं

65 हस्तियों को मिले पद्म अवॉर्ड

सिंगर अलका याग्निक, ममूटी और विजय अमृतराज को पद्म भूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में दूसरे चरण के पद्म पुरस्कार दे रही हैं। इस समारोह में देश की 65 हस्तियां सम्मानित हो रही हैं। समारोह में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस को जनसेवा और मलयालम पत्रकार पी नारायणन को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा सिंगर अलका याग्निक, एक्टर ममूटी, अमेरिका में कार्यरत प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दत्तात्रेयुडु नोरी और भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवॉर्ड दिए गए। इस साल कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से भी दिए गए हैं। 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इससे पहले 25 को पहले फेज में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत, एक्टर धर्मेंद्र समेत 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया था।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 24 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचे 'दबंग' मास्टर जी

लगाने लगे निशाना तो सहमे छात्र, प्रभारी प्रचार्य ने कराई एफआईआर

गुना (नप्र)। जिले के धरनावदा स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल में शिक्षक के हाथों में बंदूक देखकर लोग भयभीत थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुना पुलिस ने शिक्षक पर शिकंजा कसा है। प्रभारी प्रचार्य की शिकायत पर धरनावदा पुलिस ने शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक मूल रूप से राजस्थान के कवाई (सालपुरा) का निवासी है।

ढाई महीने पुराना है वीडियो- पूरा मामला करीब ढाई महीने पुराना है, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षक विनोद साहू बिना किसी खौफ के स्कूल परिसर में सरेआम बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वहां से स्कूल की प्रिंसिपल और कुछ अन्य लोग भी गुजरते हैं, लेकिन वह बेखौफ होकर हथियार लहराता रहता है। सहकर्मियों और स्थानीय नागरिकों की मानें तो आरोपी अक्सर दफ्तर और छात्रों पर धौंस जमाने और अपना रसूख दिखाने के लिए बंदूक लेकर स्कूल आता था।

7 अप्रैल की दोपहर मचाया था हड़कंप- थाने में

दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, यह खौफनाक वाकया 7 अप्रैल की दोपहर करीब 1 बजे का है। आरोपी विनोद साहू हाथ में बंदूक लेकर अचानक स्कूल प्रांगण में दाखिल हो गया। परिसर में खुलेआम हथियार देखकर वहां मौजूद छात्र-छात्राएं और स्टाफ दहशत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब मौके पर मौजूद प्रभारी प्राचार्य ममता सोनी, माध्यमिक शिक्षक चंद्रमोहन कुशवाह और उच्च माध्यमिक शिक्षक अंजू गुप्ता ने उसे रोकने का प्रयास किया और समझाइश दी।

● रास्ता खुला, मौका मिलते ही भारत की ओर हुए रवाना

होर्मुज में 4 महीने से फंसे थे एलपीजी से लदे 2 टैंकर

नई दिल्ली (एजेंसी)। होर्मुज में तनाव कम होने से भारत को राहत की सांस मिलने लगी है। खाड़ी देशों से कच्चे तेल और एलपीजी के टैंकरों ने अब न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के लिए भी राह पकड़ ली है। ऐसे ही दो जहाज भारत के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान संकट के कारण ये दोनों जहाज चार महीने से होर्मुज में फंसे हुए थे। नागपुर की प्रमुख निजी कंपनी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की ओर से चार्टर किए गए इन जहाजों में 22,000 मीट्रिक टन रसोई गैस लोड है। ये दोनों जहाज रविवार सुबह होर्मुज के दोबारा बंद होने से ठीक पहले वहां से बाहर निकलने में

कामयाब रहे। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के सूत्रों के अनुसार, ये दोनों जहाज एक सप्ताह के भीतर भारत के बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा, एक और बड़ी राहत यह है कि अल्जीरिया से 22,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा एक अन्य जहाज भी भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर चुका है और जल्द ही बंदरगाह पर लंगर डालेगा।

● **कप्तानों ने उठाया मौके का फायदा-** कंपनी के चेयरमैन नितिन खारा ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के बाद इस समुद्री रास्ते को कुछ समय के लिए खोला गया था। हमारे कप्तानों ने बेहद बहादुरी भरा कदम उठाया और इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे हमने राहत की सांस ली है। भारत के सबसे बड़े निजी एलपीजी बॉटलर्स में से एक, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम को इस महीने करीब 50,000 टन एलपीजी की जरूरत थी। युद्ध की शुरुआत में सप्लाई चेन टूटने के कारण कंपनी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिससे निपटने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए- चीन जा रहे दो जहाजों को अतिरिक्त रकम चुकाकर भारत की तरफ मोड़ा गया, जिनमें 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी थी। कंपनी ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिका से भी एलपीजी की स्पॉट खरीदारी की। घरेलू गैस के नए शिपमेंट्स के भारत पहुंचने से घरेलू बाजार पर बेहद सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा

● 21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कुरियन के इस्तीफे की जानकारी दी। प्रेस रिलीज में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह

पर उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हालांकि, इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है। 65 साल के कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे। वे अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। बतौर राज्यसभा सांसद 21 जून को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने उन्हें फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया था। कुरियन केरल में भाजपा के सीनियर नेताओं में एक हैं।

भवानीपुर सीट में सुरक्षित रखे जाएं चुनावी रिकार्ड

● कोलकाता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को सख्त आदेश

कोलकाता (एजेंसी)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए

कहा कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र बने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें न तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। अदालत ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश दिए हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का हमला

● जयराम रमेश बोले-ट्रंप को खुश करना बंद करें प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के भारत दौरे का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की नीति बंद

करनी चाहिए और वाशिंगटन के साथ उस व्यापार समझौते पर दबाव में आकर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए जिसका वर्तमान स्वरूप भारतीय हितों के प्रतिकूल दिखाई देता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि अमेरिका के साथ जिस स्वरूप में व्यापार समझौते पर सहमति बनी है उसका जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहा 'प्रतिबंधात्मक क्षेत्र' घोषित

धरना-प्रदर्शनों पर लगी रोक

भोपाल (नप्र)। भोपाल शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक पॉलिटेक्निक चौराहा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

नगरीय पुलिस भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार (भा.पु.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 जून 2026 से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा।

इन प्रमुख क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध

पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों और उनके बीच के स्थानों को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है-

पॉलिटेक्निक चौराहा
आकाशवाणी चौराहा
किलोल पार्क चौराहा
इन चौराहों के मध्य स्थित सभी स्थान

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

प्रशासन द्वारा इस कड़े कदम को उठाने के पीछे मुख्य रूप से आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है।

एकमात्र सुविधाजनक मार्ग

पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलों पर आने-जाने का

एकमात्र सुगम माध्यम है। शहर में इसका कोई अन्य सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

आपातकालीन सेवाओं में बाधा: इस मार्ग से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं और विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन होता है। यहाँ अक्सर होने वाले प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होता था, जिससे मरीजों के जीवन पर संकट आने की संभावना बनी रहती थी।

आम जनता को परेशानी- आए दिन विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों और समितियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलनों से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

एकपक्षीय आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई- समय के अभाव और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया गया है।

इस आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता है। उनकी संतुष्टि होने पर ही किन्हीं विशेष शर्तों के साथ इस प्रतिबंध से छूट दी जा सकेगी।

इस आदेश की प्रतिलिपियाँ भोपाल संभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और सभी थाना प्रभारियों सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी के लिए भेज दी गई हैं।

चीन और रूस से घिरा तो भारत को बना लिया 'तीसरा पड़ोसी'

● ड्रैगन ने डराया तो ऐक्शन में एस जयशंकर, दिया बड़ा तोहफा

उलानबतार (एजेंसी)। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे हैं। जयशंकर ने मंगोलिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने मंगोलिया और भारत के बीच रिश्ते को भाई-बहन जैसा बताया। इस बातचीत में मुख्य फोकस विशाल तेल रिफाइनरी पर था जिसे भारत की मदद से मंगोलिया में बनाया जा रहा है। मंगोलिया की विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण, तकनीक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, सप्लाई चेन, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बात की है। जयशंकर ने कहा कि मंगोलिया में बनाई जा रही तेल रिफाइनरी दोनों देशों के बीच भागीदारी के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जयशंकर ने बताया कि अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई दोनों ही देशों के बीच बातचीत में एक प्रमुख मुद्दा रहा।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को चीन का खुला समर्थन

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन के विदेश मंत्री वांग यी मंगलवार को दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के

साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन और भारत पड़ोसी देश हैं और ग्लोबल साउथ की प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए उनके बीच बेहतर सहयोग होना चाहिए। बता दें कि भारत 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कर रहा है।

धार, बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम में तेज बारिश

26 जिलों में भी अलर्ट; प्रदेश में सामान्य से 52 प्रतिशत कम पानी गिरा, 48 जिले पिछड़े

भोपाल (नप्र)। मानसून की रफ्तार धीमी होने से मध्य प्रदेश में जून का महीना अब तक सूखा बीता है। प्रदेश में सामान्य से 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जिससे खरीफ फसलों की बोवनी प्रभावित हो रही है।

हालांकि, मंगलवार को बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया, लेकिन किसानों का कहना है कि बोवनी के लिए अभी और पानी की जरूरत है।

प्रदेश में मानसून के एंटर होने की सामान्य तारीख 15 जून है, जिसे 8 दिन ज्यादा बीत चुके हैं। फिलहाल, अगले 2 से 3 दिन में मानसून आने का अनुमान जताया जा रहा है।

हालांकि, जून के पूरे महीने प्री-मानसून का दौर चल रहा। इसके बावजूद पूर्वी हिस्से, यानी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में औसत से 71 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी हिस्सा यानी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल में औसत से 33 प्रतिशत कम पानी गिरा है।

जबलपुर समेत 4 जिलों में लू का अलर्ट, 26 जिलों में बारिश- मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, बैतूल, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, आलीराजपुर और झाबुआ में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है।

दूसरी ओर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गर्मी का असर रहने की संभावना है।

11 साल की मासूम से रेप, फिर हत्या

● फुटपाथ से सोते वक्त उठा ले गया था टैक्सी ड्राइवर, गुब्बारे बेचती थी बच्ची

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में गुब्बारे बेचने वाली 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह फुटपाथ पर सो रही बच्ची का टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप किया था। इसके बाद उसने उसका रेप किया और हत्या कर लाश महरौली के जंगलों में फेंक दी थी। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे परिवार ने वीडियो कॉल के जरिए महरौली थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चार घंटे में ही बबलू नाम के टैक्सी ड्राइवर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने

आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सड़क से गुजरते समय उसने सीडीआर चौक के पास फुटपाथ पर बच्ची को सोते हुए देखा था। उसने नींद में ही बच्ची को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाकर महरौली के जंगलों में ले गया था, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया।

पीड़ित परिवार और आरोपी बिहार के रहने वाले

महरौली पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। परिवार पहले किराए पर रहता था। गरीबी के चलते किराया नहीं दे पाए तो घर खाली करना पड़ा। इसके बाद परिवार फुटपाथ पर ही रहने लगा था। वहीं, एप बेस्ड कैब चलाने वाला आरोपी ड्राइवर भी बिहार का ही रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से भी मारपीट और नशे में टैक्सी चलाने के कुछ मुकदमे दर्ज हैं।

योगी सरकार तक पहुंची राममंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट

● एसआईटी ने 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने बताया कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए।

5 आरोपियों से 2 करोड़ रुपए की रिकवरी - राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा, चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना मिला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा

की हो सकती है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में श्रीराम सेना ने राम जन्मभूमि थाना पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए सेवादार अनिल मिश्रा समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और नारको टेस्ट कराए जाने की मांग की। दिनेश सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई से ही करोड़ों राम भक्तों की आस्था मंदिर के प्रति बनी रह सकेगी।

केजरीवाल बोले-

● **अब तक चंपत राय को हटाया क्यों नहीं गया-** दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। राम भक्तों में बहुत गुस्सा है और मन में कई सवाल हैं। आज मैं सरकार से पहला सवाल पूछ रहा हूं। पूरे राम मंदिर का कंट्रोल चंपत राय के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप चंपत राय पर ही लग रहे हैं। उसे अब तक हटाया क्यों नहीं गया? क्या इस बात का डर है कि अगर चंपत राय ने मुंह खोला, तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।

जीआई टैग से 'इंदौरी मालवी आलू' को मिली पहचान, निर्यात के नए रास्ते खुले

इंदौर। जिले और पूरे संभाग की प्रमुख उद्यानिकी फसल 'इंदौरी मालवी आलू' को जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक) मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिली। इस मान्यता से आलू के निर्यात को गति मिलने की संभावना बढ़ गई है, वहीं किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के रास्ते भी मजबूत हुए हैं। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने और उन्हें जीआई टैग उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए प्रयासों के तहत इंदौरी मालवी आलू को यह महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। यह फसल मध्यप्रदेश की 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में भी शामिल है और जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में इंदौर जिले में लगभग 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जा रही है। इस खेती से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30 से 35 हजार किसान जुड़े हुए हैं। जीआई टैग मिलने के बाद उत्पादन क्षेत्र बढ़ने, निर्यात के अवसर विकसित होने और बाजार में बेहतर पहचान मिलने से किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

विशिष्ट पहचान के कारण मांग

उप संचालक उद्यान त्रिलोकचंद वास्कले के अनुसार इंदौर जिले की विशिष्ट जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और किसानों द्वारा अपनाई जा रही उन्नत कृषि तकनीकों ने यहां के आलू को अलग पहचान दिलाई है। इंदौरी मालवी आलू में शर्करा और स्टार्च की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसी कारण इससे बनने वाले चिप्स और फ्रेंच फाइज तलने पर काले या लाल नहीं पड़ते और उनका रंग साफ तथा आकर्षक बना रहता है। यही विशेषता इसे प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपयुक्त बनाती है।

बेहतर प्रसंस्करण क्षमता के कारण मांग बढ़ी, किसानों को लाभ

कई बड़ी कंपनियां खरीदार

अपने विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के कारण इंदौरी मालवी आलू की मांग देशभर में बनी हुई है। कई बड़ी कंपनियां जैसे आईटीसी, महिंद्रा, पेप्सिको, इस्कॉन बालाजी, मकेन्स और हायफन सीड्स सीधे किसानों से जुड़कर प्रसंस्करण योग्य आलू का उत्पादन कराते हैं तथा उचित मूल्य पर फसल खरीदते हैं। इंदौर जिले के मालवी आलू की गुणवत्ता को देखते हुए अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां इससे चिप्स, वेफर्स, फ्रेंच फाइज और अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। बालाजी, यलो डायमंड, पारले, हल्दीराम और लेस जैसी कंपनियां भी आलू आधारित उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग करती हैं। स्थानीय स्तर पर महू विकासखंड के ग्राम कोदरिया और आसपास के क्षेत्रों में आलू आधारित लगभग 250 से 300 मौसमी प्रसंस्करण इकाइयां संचालित होती हैं। इन इकाइयों में आलू चिप्स, वेफर्स, स्टार्च, पाउडर और फ्रेंच फाइज जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं।

दुनिया की दूसरी रोटी कहा जाता है

पोषण की दृष्टि से भी आलू महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे दुनिया की दूसरी रोटी कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जबकि विटामिन सी और विटामिन बी 6 रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा पोटेशियम, फाइबर, मैंगनीज, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से इंदौरी मालवी आलू की ब्रांड वैल्यू और मजबूत होगी। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग बढ़ने के साथ किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है और निर्यात के नए अवसर भी विकसित होंगे। इंदौर की जलवायु, उपजाऊ भूमि और आधुनिक खेती पद्धतियों से जुड़ी इस उपलब्धि को जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट बनी, चौकसे सिर्फ अध्यक्ष

'एक व्यक्ति-एक पद' फार्मूले पर कांग्रेस ने यह फैसला किया

इंदौर। कांग्रेस संगठन में लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बड़ा बदलाव किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को नेता प्रतिपक्ष के दायित्व से

मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह पार्षद सोनिला मिमरोट भाटिया को नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह निर्णय कांग्रेस के 'एक व्यक्ति-एक पद' सिद्धांत के तहत लिया गया है। लंबे समय से संगठन के भीतर यह मांग उठ रही थी कि चिंटू चौकसे शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां एक साथ संभाल रहे हैं, ऐसे में उन्हें किसी एक पद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रदेश नेतृत्व ने मामले पर विचार करने के बाद चौकसे को शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सोनिला मिमरोट भाटिया को उनकी सक्रियता और मुखर कार्यशैली का लाभ मिला है। नगर निगम परिषद में वे लगातार जनहित के मुद्दे उठाती रही हैं और सत्ता पक्ष को तथ्यों के आधार पर घेरने के लिए जानी जाती हैं। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस को परिषद में एक नई और आक्रामक आवाज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

चुराई बाइक का शातिर चोर धराया

इंदौर। पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा है, जो खुद ही वाहन चुराकर अपने गैरेज में उसे काटकर पार्टस बेच देता था। बदमाश से दो बाइक और कटे हुए तीन चेचिस बरामद हुए है। आरोपी ने छह दिन पहले भी बाइक चुराई थी। परदेशीपुरा पुलिस को फरियादी नरेन्द्र पिता नंदकिशोर लकवाल निवासी कुलकर्णी का भट्ठा ने बताया कि वह किसी काम से 16 जून को वाइन शॉप के पास तुलसी कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान में खरीदी करने गया था। सामान खरीदी के बाद जब वह लौटा तो उसकी बाइक (एमपी-09-वीडी-0441) दिखाई नहीं दी। आसपास भी उसने बाइक ढूंढी। काफी देर तक जब बाइक का पता नहीं चल सका तो पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज में आए हुलिए के आधार पर आरोपी की पहचान आरोपी मुकेश कुल्हार निवासी गणेश नगर, परदेशीपुरा के रुप में हुई। आरोपी को पकड़ा तो उसने बाइक चुराना कबूला। यह भी बताया कि उसका बाणगंगा थाना क्षेत्र के भानगढ़ में आटो गैरेज है। वह बाइक चुराने के बाद उसके पार्ट्स काटकर बेच देता है। वाहनों की नंबर प्लेट भी बदल देता था, ताकि वाहनों की पहचान न हो सके। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है।

लोन दिलाने का झांसा, महिला से ठगी

इंदौर। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में महिला से लोन दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 43 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी ने महिला से प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज के नाम पर पैसे लिए थे। शिवधाम कॉलोनी निवासी मीना राठौर ने बताया कि उनके पति गणेश लॉज और होटल व्यवसायी हैं। डेढ़ वर्ष पहले संतोष वर्मा नामक युवक उनके होटल पर खाना खाने आता था। कई बार लॉज में भी ठहरा था। इसी दौरान उसकी परिवार से पहचान हो गई। बातचीत के दौरान संतोष ने दावा किया कि वह कई लोगों को लोन दिला चुका है। उसने नामी रिसॉर्ट के शेफ का लोन मंजूर कराने का उदाहरण देकर पीड़ितका का विश्वास जीत लिया। इसके बाद उसने भरोसा दिलाया कि वह उनको भी लोन दिला सकता है। आरोपी ने लोन प्रक्रिया आगे बढ़ाने, दस्तावेजों की फाइल तैयार करने और विभिन्न शुल्कों का हवाला देते हुए कई बार भुगतान करवाया। काफी समय बीतने के बाद न तो लोन मिला और न ही जमा की गई राशि। जब महिला ने आरोपी से अपने पैसे लौटाने की मांग की तो वह बहाने बनाता रहा। इसके बाद पीड़िता को अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस की शरण ली।

बाइक पर बीयर पीने वाले गिरफ्तार

इंदौर। सोशल मीडिया पर स्टंट करना युवकों के लिए शगल बन चुका है। ऐसे युवकों के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कड़ा सबक भी सिखाती है। इसके बावजूद युवक-युवती मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को विजयनगर थाना क्षेत्र में दो बाइक पर दो युवक-युवती थे। युवतियां चलती बाइक पर बीयर पीती और सिगरेट के कश लगा रही थी। युवतियों की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हुई और कैमरे में कैद बाइक के नंबर के आधार पर युवक-युवती की पहचान की। चारों युवक-युवतियों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने चारों को सबक सिखाया तो वे अपनी गलती मानते हुए माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली है। साथ ही युवक-युवती को चेतावनी दी कि आगे से इस तरह की हरकत की तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीट प्रभारियों को अपराध नियंत्रण पर जोर

इंदौर। बीट स्तर की पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर ने जोन-2 के लसूडिया थाना के बीट प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। इसमें अपराध नियंत्रण, जनसंतुष्टि, सामुदायिक पुलिसिंग और साइबर अपराधों की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर ने 1 जनवरी से 15 जून तक पिछले तीन वर्षों के अपराध आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा की। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए बीट प्रभारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। बीट प्रभारी पुलिस और जनता के बीच मजबूत कड़ी है, जिनकी सक्रियता से न केवल अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है बल्कि आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाई जा सकती है। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बीट में नियमित भ्रमण किया जाए। माइक्रो बीट पुलिसिंग को सशक्त बनाया जाए। हर गतिविधि पर निगरानी रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए। थाना स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की नियमित समीक्षा कर उनकी कार्यशीलता बनाए रखें।। हर फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए।

गांधीनगर में डीजे संचालकों की बैठक

इंदौर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर गांधीनगर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एसीपी निधि सक्सेना के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इसमें में शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। एसीपी ने डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किया जाए। निर्धारित समय सीमा, ध्वनि स्तर तथा प्रशासनिक अनुमति संबंधी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित संचालकों से त्योहारों के दौरान प्रशासन का सहयोग करने, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की गई। सभी संचालकों ने निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।

शिशुकुंज स्कूल का किचन सील किया जांच में एक्सपायर खाद्य सामग्री मिली

बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायत, 23 खाद्य नमूने लैब भेजे गए

इंदौर। पूर्वी बायपास के नजदीक शिशुकुंज स्कूल के भोजन से बच्चों की तबीयत खराब होने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के किचन को आगामी आदेश तक सील कर दिया है। जांच के दौरान एक्सपायरी डेट पार कर चुके मसाले और अन्य खाद्य सामग्री मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। जानकारी के अनुसार, अभिभावकों द्वारा कलेक्टर शिवम वर्मा को स्कूल में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। शिकायत प्राप्त होते ही कलेक्टर के निर्देश पर एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया, जिसने स्कूल परिसर में पहुंचकर किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जांच दल ने भोजन तैयार करने और संग्रहित करने में उपयोग की जा रही विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए। इनमें पनीर, आइसक्रीम, 6 प्रकार के मसाले, शरबत, राजमा, तेल, नमकीन, 4 प्रकार की दालें, दूध, तैयार दाल, तैयार कोफ्ते, कोफ्ते की सब्जी, पके हुए चावल, रोटी तथा पीने के पानी सहित कुल 23 खाद्य सामग्री के नमूने शामिल हैं। सभी नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

एक्सपायर्ड मसाले मिले

जांच के दौरान किचन में कई अनियमितताएं भी सामने आईं। अधिकारियों को एक्सपायरी डेट निकल चुके मसालों के 10 पैकेट और नमकीन के 2 पैकेट मिले। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रकरण तैयार किया गया और किचन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम कनाड़िया दीपक चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माधव प्रसाद हासानी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

शिकायत के लिए नंबर जारी

कलेक्टर ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी स्कूल, हॉस्टल, मेस, कैंटीन या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में गंदगी, मिलावट, अस्वच्छ व्यवस्थाएं, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनियमितता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 पर दें।

एसीपी पर अभद्रता और जातिसूचक टिप्पणी के आरोप की शिकायत की

माफी और निलंबन की मांग, निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन

इंदौर। कलेक्टर कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। सोमवार को महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ता विशेष पुलिस थाना अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पहुंचीं और एसीपी तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एसीपी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा जातिसूचक टिप्पणी की। कांग्रेस नेत्रियों का कहना है कि इस घटना से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिला मीमरोट भाटिया, कांग्रेस नेता शशि हाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष रीता डांगरे सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल रहीं। उन्होंने मांग की कि एसीपी सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक आंदोलन शुरू करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुछ महिला कांग्रेस पदाधिकारियों पर भी प्रकरण दर्ज किया था। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और चर्चा में आ गया है।

मौसम बिगड़ने पर विद्युत आपूर्ति बिगड़े तो तेजी से सुधार के निर्देश

प्रबंध निदेशक ने कहा, अभियान गंभीरता, तत्परता से चलाएं

इंदौर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि मालवा निमाड़ में भी मानसून की सक्रियता की स्थिति बनने लगी है, अलग अलग जिलों में अलग समय में तेज हवा, आंधी, वर्षा हो रही है। यदि मौसम बिगड़ने से यदि विद्युत आपूर्ति व्यवधान की स्थिति निर्मित होती है तो बिजली कंपनी जोन, वितरण केंद्र प्रभारी तुरंत संज्ञान लेकर कम समय में आपूर्ति सामान्य करने की कोशिश करे। अतिरिक्त टीमें लगाकर सुधार कार्य कम समय में कराया जाए, आपूर्ति सामान्य करने का अभियान पूरी तन्मयता, गंभीरता, तत्परता के साथ चलाया जाए। उच्च दाब संकाय के कार्मिकों की भी मदद ली जाए, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री प्रभावित क्षेत्रों का सतत पर्यवेक्षण करे एवं अतिरिक्त साधन, कार्मिक मुहैया कराने में मदद करे। सिंह ने कहा कि मौसमी कारण, पेड़ गिरने से व्यवधान संभव हैं, लेकिन हमारी सफलता तभी हैं जब बड़े व्यवधान को छोटी सी अवधि में सामान्य करने की सफलतम कोशिश कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए। सिंह ने कहा कि जिस जोन, वितरण केंद्र की बिजली आपूर्ति पेड़ गिरने, आंधी तूफान से प्रभावित होती है, वहां के जोन प्रभारी, सीसीआर, लाइनमैन इत्यादि कार्मिक जोन के ग्रुपों में वाट्सएप संदेश जरूर सांझा करे कि किस कारण से बिजली बंद हैं एवं कितने आंकलित समय में बिजली आने की संभावना हैं।

परिवार गोद भराई में गया, पीछे से चोरों ने धावा बोलकर माल उड़ाया

एक दिन में तीन स्थानों पर वारदात, रात्रि गश्त की पोल खुली

इंदौर। शहर में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात चोरी की तीन अलग-अलग घटनाएं हुए। इन घटनाओं ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी है। तीनों स्थानों से बदमाश लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर गए। बुराना खेड़ी में किसान का परिवार गोदभराई कार्यक्रम में गया था। जब वह घर लौटा तो गेहूं की पेटी में छिपाकर रखे आभूषण नहीं थे। खुडैल पुलिस को अर्जुन चौधरी ने बताया कि वे 18 जून को परिवार के साथ ग्राम डबलचौकी में गोद भराई कार्यक्रम में गए थे। घर लौटे तो गेहूं की पेटी का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान बिखरा पड़ा था। चोर उनके घर से सोने का हार, झुमके, मंगलसूत्र, चार जोड़ी पायजेब सहित अन्य जेवर शामिल हैं। दूसरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र के शांति फार्म हाउस इलाके का है। यहां रहने वाले राजकुमार वर्मा ने बताया कि वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं। कुछ दिन के लिए अपने ससुराल गए थे। रविवार को घर लौटने पर देखा कि मकान का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। बदमाश सोने का हार, टॉप्स, चार सोने की अंगूठियां, पाटली, मंगलसूत्र, नथ, चांदी के जेवर और नकदी ले गए। तीसरी घटना सराफा थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाले वित्त सलाहकार आशीष जैन ने बताया कि रविवार सुबह वह नलिया बाखल क्षेत्र में सब्जी खरीदने गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात युवक ने उनकी पेंट की जेब से मोबाइल चुरा लिया। तीनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

स्कूटी को लगाई आग, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते महिला की घर के बाहर खड़ी स्कूटी को पेट्रोल डालकर बदमाश ने आग लगी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आग लगाने वाले बदमाश को दबोच लिया। फरियादी नीमा डांडिया ने बताया कि 18 जून की रात वे अपने परिवार के साथ सो रही थीं। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के बाहर खड़ी एक्टिवा स्कूटी (एमपी-09-डीबी-0576) पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह जल गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान की। मामले में पुलिस ने चंदन नगर क्षेत्र से आरोपी आदित्य पिता संतोष कोसे निवासी रामा कॉलोनी सिरपुर को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फरियादी के परिवार से उसकी रंजिश थी। बदला लेने के उद्देश्य से उसने स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

भैसलाय में 4.39 लाख की शराब जब्त

इंदौर/महू। आबकारी विभाग ने भैसलाय-पीथमपुर मार्ग पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी कार जब्त की है। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने एमपी-09-सीजे-9152 नंबर की सफेद डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया,लेकिन चालक कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी में कार से देशी प्लेन शराब के 12 कार्टन बरामद हुए। प्रत्येक कार्टन में 50 क्वार्टर रखे थे। कुल 180 बल्क लीटर शराब अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। आबकारी विभाग ने शराब और वाहन सहित 4.39 लाख रुपए का माल जब्त किया है। मामले में धारा 34(1)(ए) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में आरक्षक हुकुम सिंह पंवार और ओमप्रकाश राठौर की विशेष भूमिका रही।

भागीरथपुरा में सड़क निर्माण तेज करने के निर्देश, पानी की जांच भी

निगम आयुक्त ने जल की स्वच्छता व्यवस्था को भी परखा

इंदौर। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पेयजल, ड्रेनेज और सड़क निर्माण कार्यों की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। भागीरथपुरा में जल प्रदाय और ड्रेनेज लाइन बिछाने के बाद चल रहे सड़क निर्माण एवं रेस्टोरेशन कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने भागीरथपुरा स्थित पानी की टंकी, शासकीय विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों का भी दौरा किया।

उन्होंने रहवासियों से सीधे संवाद कर जल आपूर्ति व्यवस्था का फीडबैक लिया। नागरिकों ने नियमित पेयजल आपूर्ति और निगम की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान आयुक्त ने मौके पर ही क्लोरीन परीक्षण कराकर पानी की गुणवत्ता की जांच कराई और नियमित जल परीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जोन क्रमांक-10 के वार्ड 39 स्थित खुदा बख्श कॉलोनी और हबीब कॉलोनी में जलप्रदाय, ड्रेनेज तथा स्वच्छता व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संपादकीय

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार!

फुटपाथ पर पैदल चलना एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन आज भारत में ज्यादातर शहरों में पैदल राहगीरों के लिए बने फुटपाथ भी अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इन पर धड़ल्ले से गुमठियां तन रही हैं, ठेले लग रहे हैं तो कहीं झुग्गियां भी बन गई हैं। सरकारें फुटपाथों पर हो रहे इन अतिईक्रमणों को अनदेखा कर रही हैं। परिणामस्वरूप आज कई शहरों में फुटपाथ पर चलने की जगह राहगीरों को मुख्य सड़क पर चलना पड़ा रहा है और कई बार वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कहा है कि फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और सड़कों पर गाड़ियों से पहले आपका हक है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात को माना है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि संविधान, गरिमा और जीवन के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। कोर्ट ने कहा कि हर सड़क के किनारे सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराने, उनका रखरखाव करने और अतिक्रमण से मुक्त रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की है। यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालत से मुआवजा और अन्य कानूनी राहत भी मांग सकते हैं। यह फैसला केवल सड़कों के डिजाइन को नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं को बदलने वाला भी है। यह उन करोड़ों भारतीयों के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के अधिकार की संवैधानिक घोषणा है, जिनकी आवाज अब तक ट्रैफिक के शोर में दब जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बरसों की इस लाचारी को केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि सीधे इंसान के आत्मसम्मान और संविधान से जुड़ा यह एक ऐसा फैसला है जो भारतीय सड़कों की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। न्यायमूर्ति पामिदिघंटम नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल शरदचंद्र चांदुरकर की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) (आवागमन की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 19(1)(ए), 19(1)(बी), 19(1)(सी) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सड़क है तो उसके साथ सुरक्षित फुटपाथ होना भी अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायतों की है। इन संस्थाओं को फुटपाथों का निर्माण, रखरखाव और अतिक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि पैदल चलना सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नागरिकों को सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध नहीं कराया जाता या उसके इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह संविधान और अन्य कानूनों के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। वह मुआवजा और अन्य कानूनी राहत पाने का भी हकदार होगा। यह अधिकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मिलने वाले उपायों से अलग और स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने अपना काम कर दिया और पूरी दमदारी से किया। लेकिन असली सवाल यह है कि सरकारें और स्थानीय संस्थाएं इस पर कितनी गंभीरता से अमल करेंगीं। दुर्भाग्य से फुटपाथों पर अतिक्रमण करवाने और गुमठी, ठेले आदि लगवाने में सत्ता पक्ष और बाहुबलियों का ही हाथ होता है। ये लोग पैसा लेकर लोगों से यह सब करवाते हैं। इस कमीशन से खासी मोटी कमाई होती है। यहां तक पुलिस अथवा नगरीय निकायों द्वारा कार्रवाई किए जाने पर यही लोग फुटपाथ पर अवैध गुमठी अथवा ठेले लगाने वालों को बचाने की गारंटी भी लेते हैं। हालांकि इस तरह फुटपाथ पर दुकानें लगाने का एक मानवीय पक्ष भी है। क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों के रोजगार से भी जुड़ा है। लेकिन इसकी वजह राहगीरों से फुटपाथ छीन लिए जाएं और उन्हें जान जोखिम में डाल कर सड़कों पर चलना पड़ा, इसे तो सही नहीं ठहराया जा सकता।

केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है तापमान का संकट

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

साल 2025 में एशिया के अनेक देशों ने भीषण गर्मी की ऐसी मार झेली, जिसने जलवायु परिवर्तन के खतरे को एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। भारत, चीन, थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई हिस्सों में तापमान ने नए रिकॉर्ड बनाए। भारत के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खेतों में फसलें झुलसने लगीं, बिजली की मांग अचानक बढ़ गई और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इसी दौरान विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि एशिया दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है, जहां तापमान सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। यह केवल एक मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय की गंभीर तस्वीर है। यह संकेत है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो जलवायु संकट मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का संबंध आज किसी से छिपा नहीं है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। ये गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी के वातावरण में रोककर रखती हैं, जिसके कारण धरती धीरे-धीरे गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी देते रहे हैं कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के गंभीर परिणाम सामने आएंगे। दुर्भाग्य से दुनिया ने इन चेतावनियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितनी आवश्यकता थी।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2025 के बीच एशिया में तापमान वृद्धि की दर 1961 से 1990 की तुलना में लगभग दोगुनी रही है। यह तथ्य बताता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। वर्ष 2025 को अब तक के सबसे गर्म वर्षों में गिना जा रहा है। बढ़ते तापमान का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।

सबसे पहले यदि कृषि क्षेत्र की बात करें, तो तापमान वृद्धि का सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी और अनियमित वर्षा के कारण फसलों की उत्पादकता घट रही है। गेहूं, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलें तापमान में छोटे बदलावों के प्रति भी संवेदनशील होती हैं। जब गर्मी सामान्य सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तो फसल की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। यदि खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है, तो इसका असर केवल किसानों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं और गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है।

जल संकट भी तापमान वृद्धि का एक बड़ा परिणाम है। बढ़ती गर्मी के कारण नदियों, झीलों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से घटता है। हिमालय के ग्लेशियर, जिन्हें एशिया का जल भंडार कहा जाता है, तेजी से पिघल रहे हैं। प्रारंभिक वर्षों में इससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है, लेकिन लंबे समय में जल उपलब्धता कम हो जाती है। करोड़ों लोगों की पेयजल और सिंचाई की जरूरतें इन हिमनदों पर निर्भर हैं। यदि इनका क्षरण इसी गति से जारी रहा, तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है।

बढ़ते तापमान का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। हीट वेव यानी लू की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, हृदय रोग और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान वृद्धि की वर्तमान गति जारी रही, तो गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या आने वाले दशकों में कई गुना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त गर्म जलवायु मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को भी बढ़ावा देती है।

प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति भी तापमान संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समुद्र का तापमान बढ़ने से चक्रवात अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है, तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। एशिया के कई देशों में हाल के वर्षों में आई बाढ़ और चक्रवातों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इन आपदाओं से केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि लोगों का जीवन, आजीविका और सामाजिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ये आपदाएं विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। बढ़ते तापमान का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक है। जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं, तो सरकारों को राहत और पुनर्वास पर भारी खर्च करना पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी, उद्योगों पर प्रभाव और श्रमिकों की उत्पादकता में गिरावट आर्थिक विकास को धीमा कर देती है। अत्यधिक गर्मी में निर्माण, परिवहन और अन्य बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है। इससे उत्पादन लागत बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान अब अरबों डॉलर में आंका जाने लगा है।

जैव विविधता पर भी तापमान वृद्धि का गंभीर असर पड़ रहा है। अनेक पशु-पक्षी और वनस्पतियां अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। समुद्र के गर्म होने से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं, जिन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे वन्यजीवों का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। यदि जैव विविधता का यह नुकसान जारी रहा, तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है और मानव जीवन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। अब सवाल है कि जब खतरे इतने स्पष्ट हैं, तब भी प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। इसका एक कारण विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कठिनाई है। कई देश आर्थिक विकास की दौड़ में पर्यावरणीय चिंताओं को प्राथमिकता नहीं दे पाते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जलवायु समझौतों को लागू करने में राजनीतिक और आर्थिक मतभेद सामने आते हैं। हालांकि पेरिस समझौते जैसे प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अभी भी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

इस संकट से निपटने के लिए सरकारों, उद्योगों और आम नागरिकों सभी की साझा जिम्मेदारी है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करनी होगी। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण समय की मांग है। शहरों की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि हरित क्षेत्र बढ़ें और तापमान नियंत्रण में मदद मिले। जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना होगा। साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। भारत के संदर्भ में यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां बड़ी आबादी कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर समुदायों को जलवायु अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा।

तापमान का संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व, विकास और भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न है। बढ़ती गर्मी हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ असंतुलन की कीमत बहुत भारी होती है। यदि आज भी दुनिया ने चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे ग्रह का सामना करना पड़ेगा जहां प्राकृतिक संसाधन सीमित होंगे, आपदाएं अधिक होंगी और जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगा। इसलिए यह समय बहस का नहीं, बल्कि ठोस और सामूहिक कार्रवाई का है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष केवल सरकारों का दायित्व नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा जिम्मेदारी है। तभी हम बढ़ते तापमान के इस संकट को नियंत्रित कर एक सुरक्षित और संतुलित भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

क्या नज़ीर की मॉब लिंचिंग बन पाएगी नजीर

सामयिक

डॉ.संजीव कुमार
लेखक सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।

14 जून को मॉब लिंचिंग के इतिहास में पहली मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के जिला न्यायालय द्वारा एक साथ 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुकदमे का निर्णय न्यायाधीश तबस्सुम खान के द्वारा सुनाया गया है। चूंकि मामला हिंदू मुस्लिम पक्ष से जुड़ा है और निर्णय एक मुस्लिम महिला द्वारा सुनाया गया है जिसका तथाकथित गौरक्षक समाज सोशल मीडिया तथा अन्य तरीकों से विरोध कर रहा है वहीं संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

बात 3 अगस्त 2022 की हैं। नज़ीर अहमद अपने दो साथियों के साथ महाराष्ट्र से अपने ट्रक में 25 से 30 गाय और बछड़े लेकर उन्हें बाजार में बेचने (व्यवसायिक) के लिए निकले थे। मध्य प्रदेश के नर्मदा पुरम में रात्रि लगभग दो से तीन बजे तथाकथित गौरक्षक उनके ट्रक को घेर कर रोक लेते हैं और संदेह की बुनियाद पर तीनों को पीटने लगते हैं तथा उन्हें जोर-जोर से धार्मिक नारे लगाने के लिए कहते हैं और खुद ही इसका वीडियो भी बनाते हैं और समाज में इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। दर्जनों लोगों द्वारा हिंसक मारपीट की वजह से अंततः 55 वर्षीय नजीर की कुछ दिनों बाद अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। अब लगभग चार वर्ष पश्चात् इसका निर्णय आता है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है।

सभी 14 अपराधी बहुत ही सामान्य परिवार से है। यह सभी हिंदू राष्ट्र और गौ रक्षा के नाम पर अंततः अपना जीवन तो बर्बाद कर ही चुके हैं उसके साथ-साथ अपने परिवार का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यह समाज के ऐसे नवयुवकों में से हैं जो तर्क का विवेक खो चुके हैं। इनके पास ना ही कोई अच्छी शिक्षा है और ना ही इतनी संपत्ति जिसके दम पर यह अच्छा जीवन जी सके। कमोवेश हिंदू राष्ट्र और गौ रक्षा के नाम पर जितने भी नवयुवक इस तरह का अपराध कर चुके हैं या कर रहे हैं यह सभी साधारण परिवार से और तथाकथित उच्च जातियों द्वारा ही बरगलाए गए हैं। पिछले एक दशक से मॉब लिंचिंग के मामलों ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसके पहले ऐसे शब्दों का पहले कभी प्रयोग नहीं था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले भारत में कोई अपराध नहीं होते थे या फिर इस तरह की हत्याएं नहीं होती थी। देश में इन घटनाओं से पहले भी बड़े-बड़े अपराध और सामूहिक हत्याएं हुई है। बेलछी कांड, हासिमपुर हत्याकांड, लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड जैसे बड़े-बड़े सामूहिक नरसंहार हुए हैं पर लिंचिंग का मामला इनसे अलग है। क्योंकि पूर्व में हुए सब अपराध जाति और मजहब की दुर्भावना से होते थे पर अब 'गाय रक्षा' के नाम पर होने वाले इस जातीय तथा धार्मिक विद्वेष से किए गए इस अपराध ने समाज में एक नई भाषा को जन्म दिया है जिसे आज हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। यानी अंधी भीड़ द्वारा बेवजह किसी की निर्मम हत्या।

पिछले एक दशक में गौ रक्षा के नाम पर इतने जघन्य अपराध हुए हैं जिनके वीडियो और फोटो देखकर हमारे कलेजे दहल जाते है। मन में यही सवाल होता है कि आखिर यह लोग कौन हैं, क्या उनके परिवार और समाज ने इन्हे खुला छूट दे रखा हैं ऐसा अपराध करने के लिए? और अपराध भी ऐसा कि खुद अपराधी मजे से हिंसा करते हैं और उसका वीडियो भी वायरल करते हैं। इन लोगों के लिए कानून जैसे मजाक बन चुका हैं। ऐसा इसलिए है कि इन अपराधों के बाद यह लोग कुछ ही महीनो में बरी हो जाते है और तथाकथित इनके गौरक्षक समाज द्वारा इनका फूल माला से स्वागत किया जाता है। दरअसल गौ रक्षा अथवा गौ सेवा जैसा इनका कोई कृत्य नहीं होता। इनके आकाओं को मुसलमानों और दलितों के नाम पर भड़काने तथा लड़ाने के लिए एक हथियार चाहिए। जिसके लिए यह कभी गाय तो कभी गंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गाय की यह सचमुच सेवा करना चाहते हैं या उसकी रक्षा करने का इन्होंने बिड़ा उठाया है तो पिछले 10 सालों का आंकड़ा उठा कर देख ले जितनी दुर्दशा पिछले 10 सालों में गायों की हुई है उतना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

अभी ताजा मामला जैसलमेर के राजस्थान का है जहां हजारों गायों के भूख और बीमारी से मरने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। जनवरी में चंडीगढ़ में 100 गायों की मौत हुई, छतरपुर में 50 गाए मरी, भीमपुरा राजस्थान में सैकड़ों से ज्यादा गाएँ मरी, 2024 -25 में श्रावस्ती और ललितपुर मैं सैकड़ो गायों के मरने से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। यह सब मौते प्रशासनिक देखरेख और गौशालाओं में हुई है जहां के लिए सरकार विधिवत बजट पास कर रही है।इसके अतिरिक्त सड़कों,गलियों में जो लाखों गायें भूख ,बीमारी,से दर ब्दर भटक रही है उसका तो कोई हिसाब ही नही। अगर गौ रक्षों तथा इसके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जरा भी इनकी चिंता है तो सचमुच उनके लिए उचित प्रबंध करें। और इसके लिए किसी दिखावे तथा हंगामे की भी जरूरत नहीं है। बस जो लोग भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, इन गायों को दया के नाम पर दो रोटी देते हैं वे सभी इन्हें अपने घर में पाले इनकी सेवा करें। शनिवार और सोमवार को दो गुड़ और दो रोटी से इनका पेट नहीं भरने वाला।

अब लौटते हैं मॉब लिंचिंग के मामले पर। 2015 में मोहम्मद अखलाख का मामला आप शायद भूल गए हो उनके परिवार पर गौ मांस खाने का झूठा आरोप लगा करके ग्रामीणों ने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला। 2017 में राजस्थान के अलवार में पहलू खान को गौ तस्करी के नाम पर भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। 2017 में हरियाणा की एक लोकल ट्रेन में 16 वर्षी जुनैद खान को भी इसी तरह की अफवाह की वजह से मार दिया गया था। झारखंड में भी बच्चा चोरी के नाम पर इसी प्रकार मुसलमान की लिंचिंग की गई थी। 2002 में हरियाणा में भी पांच दलितों की गौ रक्षकों ने कुछ इसी प्रकार के मामले में हत्या की थी। ऊना कांड भी इसी प्रकार का मामला है। इन सभी मामलों में हजारों से ज्यादा लोग दोषी और अपराधी है, इनमें से ज्यादातर लोग आज अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं।

पर नजीर के इस मुकदमे ने मॉब लिंचिंग केस को एक नया मोड़ दे दिया है। देश में एक आशा का सृजन होते दिखाई दे रहा है।क्योंकि भीड़ द्वारा बढ़ते हुए ऐसे अपराध को रोकने के लिए भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को पहली बार अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। धारा 103(2) ब्व्हस् के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाता है। जज तबस्सुम खान ने इसी कानून के हवाले से नज़ीर के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुने है।अब देखना ये है कि क्या नज़ीर का यह मामला एनी मॉब लिंचिंग के लिए भी एक 'नज़ीर' बन सकता है।

मंदिरों का भी होता है पुनर्जीवन

विरासत

आशीष प्रताप मावई
लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी हैं।

यह उन 206 मंदिरों की कहानी है, जो मुरैना ज़िले के हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर चंबल की झाड़ियों में बसे पढ़ावली गाँव में स्थित हैं। एएसआई द्वारा इन 206 मंदिरों में से लगभग 100 मंदिरों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। छठी से नौवीं शताब्दी के बीच गुर्जर-प्रतिहार राजाओं द्वारा निर्मित ये बटेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर समूह से भी लगभग 200 वर्ष पुराने हैं।

इन मंदिरों के नष्ट होने की दास्ताँ बड़ी अजीब है। कुछ पुरातत्वविदों का यह विचार है कि 13वीं शताब्दी में आए किसी भयानक तूफ़ान या भूकंप के कारण ये मंदिर मिट्टी में मिल गए थे। वहीं, कई इतिहासकार इसके उलट मानते हैं कि इल्तुतमिश जब अपनी सेना लेकर दिल्ली से ग्वालियर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसने इन मंदिरों को तहस-नहस कर दिया था।

लेकिन मेरा व्यक्तिगत तर्क यह है-अगर इस इलाके में कोई भीषण तूफ़ान या भूकंप आया होता, तो 10वीं शताब्दी में बनाई गई गाँव में स्थित 'गढ़ी पढ़ावली' भी नष्ट हो जाती; जबकि गढ़ी का बाहरी ढांचा आज भी जस का तस खड़ा है। हाँ, यह ज़रूर है कि उसके अंदर के मंदिर और मूर्तियाँ पूरी तरह खंडित हैं।

इसके प्रमाण बगल के ऐतिहासिक गाँव कुंतलपुर जो अब कुतवार है में भी मिलते हैं। यह माता कुंती का मायका है, जहाँ उन्हें सूर्य-पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने कर्ण को यहीं बहने वाली आसन नदी में बहाया था। इस गाँव में भी प्राचीन ऐतिहासिक ढांचे आज तक सुरक्षित खड़े हैं। इन बिखरे हुए मंदिरों के एक-एक ईंट-पत्थर को जोड़कर इन्हें पुनर्जीवित करने का श्रेय एएसआई के के.के. मोहम्मद को जाता है।

मंदिर इतनी बड़ी संख्या में हैं कि देखने से लगता है मानो यह 'मंदिरों का कुंभ' हो। इतनी बड़ी संख्या को देखकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि यह स्थान कोई महान तीर्थ रहा होगा।

मंदिर परिसर में दो पानी से लबालब भरे कुंड भी हैं जिन्हें एएसआई ने खोजा है; तीर्थयात्री संभवतः इन कुंडों में स्नान कर मंदिर में पूजा-अर्चना करते होंगे। सुबह और शाम आपको प्रांगण में मोर पंख पसारकर नाचते हुए दिख जाएँगे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे इन मंदिरों को निहारकर कह रहे हों-'चिंता मत करो, तुम्हारा निकट भविष्य तुम्हारे अतीत जैसा ही वैभवशाली होगा।'

हमारा समाज अपनी सभ्यता को भुलाकर आज किस मुहाने पर खड़ा है? बटेश्वर का सिर और आधा धड़ अभी भी ज़मीन पर खील-बताशों की तरह मूर्तियों के रूप में बिखरा हैं।

हमारे ही अपने पुरखे जो अपनी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए यह धरोहर हमारे नाम छोड़ गए, लेकिन क्या हमारी इतनी भी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने देवताओं के स्थानों को वह मान-सम्मान सूत-समेत वापस लौटाएँ, जिसके वे हकदार थे?

सोचो, अगर कोई 5 फुट 6 इंच का, उत्तर भारत के लोगों के रंग से अधिक साँवले रंग का, धर्म का मुस्लिम के.के. मोहम्मद केरल से नहीं आया होता, तो आज बटेश्वर में खंडित पड़े इस मलबे को कौन पोषित करता? जब मैंने पहली बार उस प्रांगण में प्रवेश किया, तो मेरी रूह में रेंगता खून मानो रुक सा गया हो। मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर विस्मय भरे

भाव से घूमता रहा। मैं सोच रहा था कि वह कौन दुष्ट होगा जो इन मंदिरों को उजाड़ गया! जैसे जेठ आते-आते खेत उजड़ जाते हैं, रातों-रात आगजनी से अमेज़न के जंगल उजड़ जाते हैं, तेज़ धूप से कई पोखर उजड़ जाते हैं, और युवावस्था में पति की मृत्यु से एक सुहागन महिला की ज़िंदगी उजड़ जाती है। वैसे ही बटेश्वर की ये खंडित, टूटी-फूटी मूर्तियाँ विधवा हो गईं, जो कभी पार्वती के रूप में शिव की अर्धांगिनी थीं। मैं अपने मुँह में आए कड़वे घूँट को बार-बार पिए जा रहा था, जैसे बटेश्वर के वे मंदिर मुझसे कुछ हिसाब माँग रहे हों।

मेरे लिए वे मंदिर, पवित्र तीर्थ हैं... पवित्र तीर्थ!

जो कुछ 100 मंदिर पुनर्जीवित हो चुके हैं, उन्हें भी आज के 'इल्तुतमिश, महमूद गज़नवी, औरंगज़ेब और अलाउद्दीन खिलजी' नष्ट करने पर तुले हैं। पूरा इलाक़ा खनन माफिया की चपेट में है। माफिया पहाड़ों में चट्टानों को तोड़ने के लिए भारी-भरकम ब्लास्ट करते हैं, जिससे पैदा होने वाला कंपन इन प्राचीन मंदिरों में दरारें पैदा कर रहा है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

थप्पड़ से नहीं, आपके वॉट्सएप स्टेटस से लगता है

व्यंग्य

सिंधु कन्हौआ
लेखक व्यंग्यकार हैं।

आबादी का एक खास समूह अधिकांश वक्त और अधिकांश लोगों से अमूमन आक्रोशित ही रहता है। इन नाखुश बंदों की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उलाहनों, ताने तिश्कों और शिकवा-शिकायतों में बीतता है। नाते रिश्तेदार, सहकर्मी, अड़ोसी पड़ोसी, गली मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि राह चलते लोग भी आए दिन इनके आक्रोश का शिकार बनते रहते हैं।

पहले इन शूरवीरों को भांति भांति की शिकायतों और व्यंग्य बाणों के जखीरे लेकर साथ हर संबंधित शख्स के पास तशरीफ ले जाने का कष्ट करना पड़ता था भला हो तकनीक का जो अब इन्हें वर्क फ्रॉम होम का सुभीता भी मिल गया। अब पैर पटकते हुए खुन्नस निकालने कहीं नहीं जाना है। रोजमर्रा की अदावतों, उलाहनों, शिकवा शिकायतों के त्वरित वमन के लिए सर्वाधिक सुलभ, लोकप्रिय मंच वाट्सएप है न इनके पास। अब लपलपाती जबानों का कारोबार उँगलियों के पोरों के मार्फत रिसते हलाहल ने बखूबी संभाल लिया। वाट्सएप स्टेटस पर किसिम किसिम की कुंठा, नफरत, छिद्रान्वेषण और आक्रोश के धारदार तमंचे चमकाने के नायाब दिन आ गए हैं। अलसुबह से अलसुबह तक चौबीसों घंटे, सातों दिन अलग अलग टाइम जोन में सक्रिय शूरवीरों को यहाँ अपनी भड़ास निकालने का पूरा स्कोप मिलता है। कतिपय दिलजलों के स्टेटस से तो कई बार पूरा मोबाइल ही थर्रा जाता है। लिफाफा देखकर मजमून भांपने में पारंगत कौम अब स्टेटस देखकर मिजाज भॉपने में सिद्धहस्त हो चली है।

इस स्टेटस युद्ध से कई दिलचस्प पहलू निकलकर आते हैं एक तो यह कि स्टेटस धारक का असल शिकार स्टेटस देखते ही तिलमिलाकर दूसरी ओर से भी बौखलाहट भरी बमबारी शुरू कर देता है। आत्ममुग्धता, दंभ, नुक्ताचीनी के छर्रे दोनों छोरों से दनदनाने लगते हैं। दूसरा मजेदार पहलू यह भी कि कई बार निशाना तो किसी एक पर साधा जाता है पर, कहीं ये मैं तो नहीं- किस्म के शक ओ शुब्हा के चलते मित्र सूची में मौजूद न जाने कितने बंदे खौलने खदबदाने लगते हैं। यकायक देखते ही देखते न जाने कितने कोनों से जहरीले नश्तर स्टेटस की शक्ल में चस्पा होने लगते हैं। जहर बुझे तमाम नश्तर कटूक्तियों की मारक मिसाइलें दनदनाने लगती हैं। कई बार यही शौर्य भरभराकर स्टेटस से कूद फांदकर विभिन्न समूहों तक भी पहुंच जाता है और देखते ही देखते अदना सी स्क्रीन अखाड़े में तब्दील हो जाती है।

पराए लड़ाई झगड़े देखने का अपना अलहदा आनंद है जैसे अड़ोस-पड़ोस या गली-मोहल्ले में किसी को झगड़ते देखकर आस पास वाले अपना अपना कामधंधा छोड़कर खिड़की दरवाजों से ताका-झाँकी करने लगते हैं वैसे ही संपूर्ण मित्र सूची इस मजमे का लुत्फ उठाती है। तकनीक ने इन्हे भी तो सुभीता दे रखा है,घर बैठे फ्री फोकट के शो का आनंद उठाने का। तमाम फुरसतियों का दिन बन जाता।

एक अन्य मजेदार पहलू यह भी कि कुछ घनघोर शिकायती, नैराश्य और दुख दर्द की कुनैन में पोर पोर पगे बंदों को दीवारों से मिलकर रोना इतना अच्छा लगता है कि वे अलसुबह से वाट्सएप की स्टेटस रूपी दीवार से मिलकर भी इतना रोते कलपते हैं कि कइयों की सुबह की चाय कसैली हो जाती है,तमाम आशंकाएं उनके प्याले में डूबने उतराने लगती है और इस फ़ानी दुनिया से उनका भरोसा उठने लगता है। हालांकि जल्दी ही उन्हेड्ड समझ आ जाता है कि अगला है ही रोतले मिजाज वाला प्राणी, इसकी ज्ञानवाणी को गंभीरता से लेने का नई।

और अंत में प्रणम्य हैं वे तमाम प्रतिभाशाली कला साधक भी जिनके जिक्र के बगैर यह अफसाना अधूरा रहेगा,ये बंदे बेहद मनोयोग से नित नए नश्तर की मानिंद नुकीले,जहर बुझे,बजबजाते,नकारात्मक संदेश खोजते हैं, तकनीक की मदद से इनका रंग रोगन,चित्रांकन करते हैं। कुछ होनहार बंदे अपने ही हुनर से नित नए मौलिक जले कटे, धारदार संदेशों की नियमित आपूर्ति करते हैं। ये तमाम संदेश सोशल मीडिया के बाजार में हाथों हाथ लिए जाते हैं और दनदनाकर अग्रेषित किए जाते हैं,पलक झपकते ही ये संदेश तमाम स्क्रीनों पर चस्पा होने लगते हैं। सुधीजनों द्वारा इन्हे अपने फोन की गैलरी में आड़े वक्त के लिए बाकायदा सहेजकर रखा जाता है,और यथा अवसर इनका उपयोग किया जाता है। इन साधकों के सौजन्य से हो रही असीमित आपूर्ति की बदौलत वाट्सएप के ये अखाड़े गुलजार हैं और निरंतर फल फूल रहे हैं।

मुद्दा

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुक्षेरे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

यूसीसी : संवैधानिक संकल्प से सामाजिक समरसता तक

समान नागरिक संहिता का तात्पर्य ऐसे समान नागरिक कानूनों से है जो देश के सभी नागरिकों पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान रूप से लागू हों। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक संबंधों से जुड़े अनेक मामलों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) लागू हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुसलमानों के लिए शरीयत आधारित व्यक्तिगत कानून, ईसाइयों के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम तथा पारसी समुदाय के लिए पृथक वैवाहिक और पारिवारिक कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन सभी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक ऐसा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो। यह समझना आवश्यक है कि UCC का संबंध धार्मिक पूजा-पद्धति, उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों या आस्था से नहीं है। इसका संबंध केवल नागरिक जीवन के उन पहलुओं से है जो विवाह, परिवार, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े हैं। इसलिए इसे धार्मिक हस्तक्षेप के बजाय नागरिक अधिकारों की समान व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए।

एक देश, एक संविधान और एक समान न्याय व्यवस्था ही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। जब नागरिकों के अधिकार धर्म, पंथ और संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि समान नागरिकता के आधार पर निर्धारित होते हैं, तभी राष्ट्र सशक्त और समरस बनता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां विविध धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन पद्धतियां सहस्राब्दियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। यही विविधता भारत की शक्ति भी है और उसकी विशिष्ट पहचान भी। किंतु इस विविधता के बीच संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के माध्यम से राज्य को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने का निर्देश दिया गया।

आज स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बाद यह विषय पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। विशेष रूप से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने के बाद यह चर्चा और अधिक प्रासंगिक हो गई है। यह केवल एक विधिक सुधार का विषय नहीं है, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता और आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ा व्यापक प्रश्न है।

समान नागरिक संहिता का तात्पर्य ऐसे समान नागरिक कानूनों से है जो देश के सभी नागरिकों पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान रूप से लागू हों। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक संबंधों से जुड़े अनेक मामलों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) लागू हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुसलमानों के लिए शरीयत आधारित व्यक्तिगत कानून, ईसाइयों के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम तथा पारसी समुदाय के लिए पृथक वैवाहिक और पारिवारिक कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन सभी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक ऐसा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो।

यह समझना आवश्यक है कि UCC का संबंध धार्मिक पूजा-पद्धति, उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों या आस्था से नहीं है। इसका संबंध केवल नागरिक जीवन के उन पहलुओं से है जो विवाह, परिवार, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े हैं। इसलिए इसे धार्मिक हस्तक्षेप के बजाय नागरिक अधिकारों की समान व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर विस्तृत चर्चा हुई थी। संविधान निर्माता मानते थे कि भविष्य में भारत को एक समान नागरिक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर का स्पष्ट मत था कि एक आधुनिक राष्ट्र में नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार धर्म आधारित भिन्नताओं पर निर्भर नहीं होने चाहिए। उन्होंने माना कि राज्य को सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का अधिकार और दायित्व दोनों हैं। इसी सोच के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

भारत में व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान व्यवस्था का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने आपराधिक कानूनों को तो एक समान बनाया, लेकिन विवाह और पारिवारिक मामलों में धार्मिक समुदायों के अलग-अलग कानूनों को जारी रखा। स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था काफी हद तक बनी रही। 1955-56 में हिंदू कानूनों में व्यापक सुधार किए गए, लेकिन सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून नहीं बन पाए। परिणामस्वरूप आज भी भारत में नागरिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों द्वारा संचालित होते हैं।

समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता सबसे पहले संविधान की मूल भावना को साकार करने के लिए है। भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। जब सभी नागरिक मतदान करने, कर देने और आपराधिक कानूनों का पालन करने में समान हैं, तो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग कानूनों का औचित्य स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनता है। UCC संविधान की समानता की भावना को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम बन सकता है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा भी UCC की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में व्यक्तिगत कानूनों के कारण कई बार महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में असमान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। समान नागरिक संहिता महिलाओं को समान कानूनी अधिकार प्रदान करने, संपत्ति में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, विवाह और तलाक के मामलों में समान सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा लैंगिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दृष्टि से UCC को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार माना जा रहा है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भी UCC का विशेष महत्व है। एक राष्ट्र में नागरिकों के लिए अलग-अलग नागरिक कानून होने से कभी-कभी कानूनी और सामाजिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। समान नागरिक संहिता यह संदेश देती है कि राष्ट्र में नागरिकता सर्वोपरि है और सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान हैं। इससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और संवैधानिक राष्ट्रवाद को मजबूती मिल सकती है।

न्यायिक व्यवस्था को सरल बनाने में भी UCC महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण न्यायालयों को अनेक जटिल विवादों और कानूनी व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि एक समान नागरिक कानून लागू होता है तो कानूनी अस्पष्टता कम होगी, मुकदमों में कमी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल एवं प्रभावी बन सकेगी।

आज का भारत तेजी से बदल रहा है। शिक्षा, शहरीकरण, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, अंतर्धार्मिक विवाहों में वृद्धि और बदलती सामाजिक संरचना ने नागरिक जीवन को नया स्वरूप दिया है। ऐसे में नागरिक कानूनों का आधुनिक, वैज्ञानिक और समान स्वरूप समय की आवश्यकता बन गया है। विकसित भारत की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब सामाजिक न्याय और विधिक समानता भी उसके साथ-साथ आगे बढ़े।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देता रहा है। शाहबानो प्रकरण (1985) में न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए UCC की आवश्यकता का उल्लेख किया था। इसीप्रकार सर्ला मुद्गल प्रकरण (1995) में भी सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में गंभीर विचार की आवश्यकता व्यक्त की थी। न्यायालय का मत रहा है कि समान नागरिक कानून राष्ट्रीय एकता और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं।

भारत में गोवा राज्य को समान नागरिक संहिता के एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। वहां विवाह पंजीकरण, संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार से संबंधित अनेक प्रावधान सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए गोवा मॉडल को अक्सर UCC के संदर्भ में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के अध्ययन और सुझावों के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार का उद्देश्य विभिन्न समुदायों से संवाद स्थापित करना, सामाजिक एवं कानूनी प्रभावों का अध्ययन करना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक व्यवहारिक और न्यायसंगत मसौदा तैयार करना है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो मध्यप्रदेश देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

हालांकि UCC को लेकर कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे उनकी पारंपरिक धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से जनजातीय समाजों की विशिष्ट परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं को लेकर भी चर्चा होती रही है। इसलिए आवश्यक है कि UCC को लागू करते समय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जनजातीय अधिकारों और सांस्कृतिक विविधताओं का पूरा सम्मान किया जाए। किसी भी कानून की सफलता उसकी सामाजिक स्वीकार्यता पर निर्भर करती है, इसलिए व्यापक संवाद और सहमति अत्यंत आवश्यक है।

वास्तव में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विविधताओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि विविधताओं के बीच समान न्याय स्थापित करना है। यह किसी धर्म, संप्रदाय या संस्कृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की समान सुरक्षा का प्रयास है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का आधार नागरिकता होना चाहिए, न कि धार्मिक पहचान।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता भारत की संवैधानिक यात्रा का वह अध्याय है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की थी। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय प्रदान करना है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब कानून की दृष्टि से नागरिकों की समानता का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्यप्रदेश द्वारा UCC की दिशा में उठाया गया कदम केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि संविधान के अधूरे संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास माना जा सकता है।

जब कानून सबके लिए समान होगा, तब संविधान की आत्मा वास्तव में जन-जन तक पहुंचेगी। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य विविधताओं को मिटाना नहीं, बल्कि समानता, न्याय, समरसता और राष्ट्रीय एकता के आधार पर एक सशक्त भारत का निर्माण करना है। यही संविधान का संदेश है, यही आधुनिक भारत की आवश्यकता है और यही भविष्य के विकसित भारत की दिशा भी।

बाल काव्य

संस्कृति के ध्वजवाहक: बच्चों के हाथों में होनी चाहिए किताब

वह कागज की कश्ती, वह बारिश का पानी, सप्तऋषि का आसमान में देखना, गर्मियों की छुट्टी में छत पर सोना, तारे देखना,रबड़ की गेंद जो हमें बचपन में यूँ ही मिल जाती थी लेकिन आज के बचपन में मोटी रकम खर्च करने पर भी नसीब नहीं होती क्योंकि यह जो पीढ़ी है, वह न तो छत पर सोती है,न मिट्टी में खेलती है ।वह तो वर्चुअल दुनिया के सहारे बड़ी होती है। जिसके पास दुनिया की बेहतरीन सुविधाएँ हैं लेकिन वह मजा नहीं,जो हमें न भूलने वाला सबक सिखाता था।

हमें दादी और नानी की गोद मिलती थी ।वह हमें कहानी कहती थीं जिनको सुनकर संवेदनशीलता जिंदा रहती थी। हमारे जमाने का बाल साहित्य भी अब पढ़ने में नहीं आता। मोबाइल ने आज के बचपन को छीन लिया, लेकिन हम कोशिश करें तो भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला साहित्य तो रच सकते हैं।

यह विचार मुझे अनुपमा श्रीवास्तव अनुश्री की 'संस्कृति के ध्वजवाहक' बाल काव्य संकलन पढ़ते समय आया कि इस पुस्तक में वह सब है जो हमें चाहिए।

वह खेल, वह नजदीकी प्रकृति से, पार्क में खेल-कूद, चिड़ियाघर,तितली देखना, परिवार में परस्पर संवादात्मकता, भाषा, इतिहास, परंपरा, जड़ों से जुड़े हुए श्रेष्ठ जीवन मूल्य, जो भारतीय संस्कृति को उत्कर्ष प्रदान करते हैं।

इस विषय में अपनी बात में लेखिका ने लिखा है- रचनाएँ स्वयं बोलती हैं उदाहरण के लिए-

'हम बच्चे' शीर्षक से वह कहती हैं-

साथ देती है हरी- भरी प्रकृति माँ
उड़ती रंगीन तितलियाँ
और सुहानी बदलिया।
चमकता सूरज और
इन सब के साथ डूबी- डूबी
हमारी मस्तियाँ।

पाएँगे जो लक्ष्य है - इस कविता में आज के बच्चों को सही दिशा में निर्देशित किया गया है -

'बिना प्रयास सफलता मिलती नहीं
ऐसा कोई शॉर्टकट,
ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं
गाड़ना है सफलता के झंडे
बदलना है हिस्ट्री
तो समझनी पड़ेगी
सही लक्ष्य की जियोग्राफी
भावनाओं की केमिस्ट्री।'

'संस्कृति के ध्वजवाहक' कविता में वह कहती हैं-

हम संस्कृति के ध्वजवाहक संसार जगाने आए ।
सदुणों की अखंड ज्योति से अंधकार मिटाने आए।।

राष्ट्रवाद का उद्घोष करते हुए वह 'धन्य धरा भारत की' कविता में कहती हैं - जीवन को सुरभित करती

मन को पवित्र करती
आचरण को शुद्ध करती
उत्तरोत्तर आदमी से
देवत्व की ओर प्रेरित करती
भारत की यह दिव्य धरती।

वहीं 'नन्हे दीये' कविता में 'आत्म दीपो भव' का भाव और 'सत्यमेव जयते' की हुँकार है-

हौसला और संकल्प से सजे
वतन की बुनियाद हैं हम।
संस्कारों का लिबास पहनकर
गढ़ेंगे भारत का गणतंत्र अप्रतिम।।

वहीं बच्चों के गैजेट प्रेम पर भी कहीं 'मोबाइल का हॉलिडे' है तो कहीं एक नटखट तंज भी -

हम जब गैजेट्स चलाते हैं
अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं। सब ने मानी हमारी बुद्धिमानी
नानी को भी याद आ जाती है नानी!

प्रकृति का आँगन, माँ तू ही तो है, छुट्टी, नई कहानी, मेरी दीपशिखा,दशहरा, मोबाइल का हॉलिडे, मैं और मेरी डायरी, घर में संवाद ,अच्छी पुस्तक- सच्ची मित्र, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जीवन है अनमोल, पेड़ लगाए, हम जागेंगे- जगाएँगे, हम हैं नई पीढ़ी आदि शीर्षक से लिखी कविताएँ क्या संदेश देती हैं पाठक स्वयं पढ़कर सोचें कि ऐसी पुस्तक अलमीरा की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यह गंतव्य और मंतव्य से भरपूर हैं यानी इन पुस्तकों को बच्चों के हाथों में पहुँचना बहुत जरूरी है ताकि उनके अंदर अपनी परंपरा, धर्म,संस्कृति, भाषा, राष्ट्रीयता, संवेदनशीलता के बीज अधिरोधित हो सकें।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसे पढ़ कर बच्चों को ऐसा अनुभव होगा जितना हमारा अपना था और वह अपने परिवेश और समसामयिक स्थितियों से भी खुद को जोड़ पाएँगे। ज्ञानवर्धक और मनोरंजन शैली में लिखी हुई ये कविताएँ हमारी मित्र बनकर यह विवेक देती है कि हमें कैसे अपने आप को सकारात्मक, विवेकवान, शिक्षित और सुसंस्कृत बनाना है। सुंदर कलेवर, काव्यभावानुकूल सुंदर चित्र संयोजन,ग्लेज्ड पेजेज के साथ यह पुस्तक बहुत आकर्षक बन पड़ी है।

आज बच्चे जो सीख रहे हैं, वह सिंगल फैमिली के दौर की बातें हैं जहां कहानियों का कोई स्थान नहीं लेकिन अब वह समय दूर नहीं जब हम ऐसे साहित्य की तलाश करेंगे जो संस्कार दे और हमें अपनी संस्कृति से जोड़कर रखें।

रचनाकार- अनुपमा श्रीवास्तव अनुश्री
पुस्तक मूल्य- 125
उपलब्धता -फ्लिपकार्ट
प्रकाशक- समृद्ध प्रकाशन,दिल्ली

अध्यात्म

डॉ. परविंदर शर्मा

सहायक प्राध्यापक, श्री गुरु तेग बहादुर भारतीय सभ्यता एवं धार्मिक परंपरा केंद्र, बठिंडा

आत्मा की शांति: योग और धर्म का पवित्र संगम

मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज शांति की खोज है। युगों से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा है कि आत्मा को सच्ची शांति कहाँ मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे ऋषि-मुनियों ने योग और धर्म के सम्मिलन में खोजा था। जब योग और धर्म एक साथ चलते हैं, तो जीवन एक दिव्य संगीत की तरह बन जाता है जिसमें हर सांस एक राग है और हर पल एक पवित्र अनुभव करता है, धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड का नाम नहीं बल्कि धर्म का अर्थ है वह मार्ग जो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। और योग वह साधन है जिसके द्वारा इस मार्ग पर चलना संभव होता है। दोनों मिलकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं।

भारतीय दर्शन में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति 'धृ' धातु से हुई है जिसका अर्थ है 'धारण करना'। अर्थात् जो सृष्टि को, समाज को और आत्मा को धारण करे, वही धर्म है। धर्म कोई बाहरी आचरण नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है जो व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है।

'गीता में भगवान श्रीकृष्ण जी कहते है

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।' (गीता 3:35)

अर्थात् अपना धर्म, चाहे कितना भी अपूर्ण हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि धर्म व्यक्तिगत है, आत्मा की पुकार है और जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। योग शब्द संस्कृत के 'युज्' धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग का वास्तविक उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना है। महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में कहा 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अष्टांग योग के आठ अंग : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन हैं। इनमें से यम और नियम सीधे धर्म से जुड़े हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम के पाँच अंग हैं जो धार्मिक जीवन की नींव हैं।

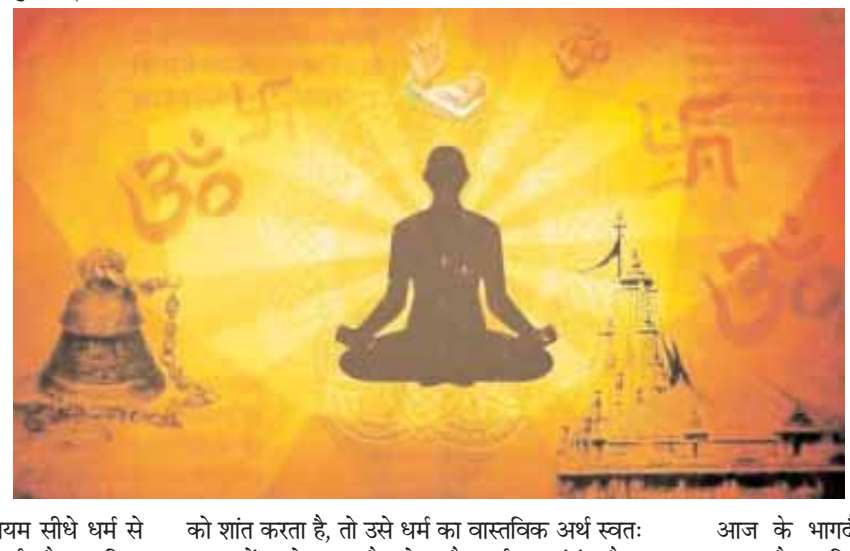

योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। यह एक समग्र जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधती है। जब कोई व्यक्ति योग के माध्यम से अपने मन को शांत करता है, तो उसे धर्म का वास्तविक अर्थ स्वतः समझ में आने लगता है। योग और धर्म का संबंध वैसा ही है जैसे नदी और उसके किनारों का। नदी का प्रवाह योग है और किनारे धर्म हैं। यदि किनारे न हों तो नदी का जल बिखर जाएगा, और यदि जल न हो तो किनारे व्यर्थ हैं। दोनों मिलकर जीवन को एक सार्थक दिशा देते हैं।

धर्म हमें बताता है कि क्या करना चाहिए सत्य बोलो, प्रेम करो, सेवा करो। और योग हमें वह शक्ति देता है जिससे हम ऐसा कर सकें। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि धर्म का पालन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। तब किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को 'योगेश्वर' कहा और गीता में ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग तथा राजयोग का विस्तृत वर्णन किया। यह स्पष्ट करता है कि योग और धर्म अलग नहीं हैं: योग ही धर्म का व्यावहारिक रूप है।

आज के भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य तनाव, अवसाद और आत्मिक शून्यता से जूझ रहा है। भौतिक सुख-सुविधाएँ होने के बावजूद मन अशांत है। इसका कारण यह है कि हमने योग और धर्म को अपने जीवन से अलग कर लिया है। यदि हम प्रतिदिन केवल 30 मिनट योगाभ्यास करें और धर्म के मूल सिद्धांतों सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा को अपने दैनिक जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। योग से शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, और धर्म से जीवन को एक उद्देश्य और दिशा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व अब योग की शक्ति को मान रहा है। भारत ने जो ज्ञान हजारों वर्षों पहले दिया था, आज वह विश्व के कोने-कोने में फैल रहा है।

योग और धर्म का यह पवित्र संगम आत्मा की शांति का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम योग के द्वारा अपने मन को साधते हैं और धर्म के द्वारा अपने जीवन को दिशा देते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। भय दूर होता है, क्रोध शांत होता है, और जीवन में एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आत्मा की यह शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं मिलती। यह तो हमारे भीतर ही छुपी है और योग व धर्म वे दिव्य चाबियाँ हैं जो इस खजाने को खोल देती हैं। इसलिए आइए, हम सब मिलकर इस पवित्र मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाएँ। 'योगः कर्मसु कौशलम्' (गीता 2:50)

(योग ही कर्मों में कुशलता है)

दिग्विजय सिंह जी के संसद में 12 वर्ष

ओमप्रकाश शर्मा

(लेखक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के निजी सचिव हैं)

जनसरोकार और मानवीय संवेदनाओं की अद्भुत यात्रा

वर्ष 1977 से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह 21 जून को राज्यसभा सांसद के पद से सेवानिवृत्त हो गये। यह उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल था और 12 साल तक उन्होंने संसद में मध्यप्रदेश और देश के लोगों की आवाज को दृढ़ता से उठाया। किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसने क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने सामान्य मानव के जीवन में श्रेष्ठतम बदलाव लाने के लिये क्या प्रयास किये हैं। व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। मानवीय संवेदनाओं ने उसे कितना स्पर्श किया। यदि इसी पैमाने पर दिग्विजय सिंह के 12 साल के संसदीय कार्यकाल की जाँच-पड़ताल की जाये तो वे जहाँ एक ओर राष्ट्र के हर कोने के व्यक्ति के जीवन को सुखद बनाने के लिये प्रयासरत दिखाई देते हैं वहीं मध्यप्रदेश के किसान, छात्र, महिलाओं, श्रमिकों, छोटे और लघु उद्यमियों, गरीबों और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की आवाज भी संसद में उठाते देखे गये हैं।

बीते 12 वर्षों में दिग्विजय सिंह जी ने संसद में कुल 1010 प्रश्न पूछे। यह अलग बात है कि उनमें से सरकार ने सिर्फ 530 प्रश्नों के उत्तर दिये हैं, शेष को अस्वीकार कर दिया। 28 प्रश्नों के उत्तर देने का आश्वासन दिया। दिग्विजय सिंह ने हर बड़े राष्ट्रीय और संवैधानिक विषयों को बहुत ही संजीदगी, जिम्मेदारी और प्रभावी तरीकों से उठाकर न सिर्फ सरकार को असहज किया बल्कि आम जनता में यह भी विश्वास पैदा किया कि उनकी आवाज संसद में वैसे ही पहुँच रही है, जैसी पहुँचनी चाहिए।

यद्यपि दिग्विजय सिंह 5 बार मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य, मध्यप्रदेश सरकार में सिंचाई, कृषि और मत्स्यपालन जैसे विभागों के मंत्री, दस वर्षों तक मुख्यमंत्री, आठवीं और दसवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं किन्तु अपने संसदीय कार्यकाल में संसद की स्थायी समितियों में रहते हुए उनके कार्यकाल को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने भारत सरकार की वित्त विभाग, गृह, कॉर्पोरेट मामलों, और शहरी आवास एवं विकास जैसी महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। संसद की नियम समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य के रूप में तथा विकसित भारत अधिष्ठान बिल सहित अनेक विधेयकों पर बनाई गई सेलेक्ट कमेटियों के सदस्य के साथ संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिये बनी संयुक्त संसदीय समिति में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किन्तु राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल में गृह विभाग की संसदीय समिति तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा और खेल विभाग की संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल सबसे अधिक स्मरणीय रहेगा।

एक राजनेता में मानवीय संवेदनाएँ भी कितनी प्रबल होती हैं, यहाँ इसका एक उदाहरण दर्शाना प्रासंगिक होगा। दिग्विजय सिंह जी वर्ष 2023 में गृह विभाग की स्थायी संसदीय समिति के सदस्य थे। इसी दौरान जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल में पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर दावा किया था कि गृह विभाग के इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी के कारण इस

हमले में 40 जवान शहीद हो गये। यह केन्द्र सरकार पर एक राज्यपाल जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का गंभीर प्रहार था जिसने मोदी सरकार को असहज कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने गृह विभाग की संसदीय समिति के सदस्य के रूप में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रजलाल को पत्र लिखा और सत्यपाल मलिक सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आई.बी. के डायरेक्टर तथा जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को समिति के सामने उपस्थित करने तथा ऑन-कैमरा मीटिंग किये जाने का प्रस्ताव रखा।

दिग्विजय सिंह ने इसके लिये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को भी पत्र लिखा। इस पत्र से न सिर्फ संसदीय समिति ही नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सभापति भी असहज हो गये। चूँकि यह विषय न सिर्फ आतंकवाद का था बल्कि सरकार की साख का भी था। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समिति प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं कर सकती।

ऐसा ही एक उदाहरण और याद आता है, जब मणिपुर में मई 2023 में प्रारंभ हुई हिंसा चरम पर थी। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था। गृह विभाग की संसदीय समिति से सूचना प्राप्त हुई कि कारागारों में सुधार को लेकर 6, 19 और 27 जुलाई 2023 को बैठकों का आयोजन किया जाना है। इस सूचना की मैंने उन्हें जैसे ही जानकारी दी, वे असहज होते हुए बोले– 'मणिपुर जल रहा है और हम जेलों की दीवारों पर चर्चा करेंगे? मैं इन बैठकों में नहीं जाऊँगा।' इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने संसदीय समिति के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें हिंसा से जलते मणिपुर के राहत शिविरों में 40 माताओं द्वारा बच्चों को जन्म देने, 250 से अधिक चर्च को जला देने, 100 से अधिक मंदिरों को आग के हवाले कर देने की भयावहता की बात कहते हुए उक्त बैठकों को स्थगित करके मणिपुर हिंसा के तत्काल समाधान निकालने के लिये बैठक करने का सुझाव दिया गया था। मैंने भी भीगी आँखों से उस दिन वह पत्र तैयार किया था।

मैंने समिति के अध्यक्ष सहित लोकसभा और राज्यसभा के सभापतियों को उसकी प्रतियाँ तत्काल ईमेल कर दीं। संसदीय समिति के अध्यक्ष की ओर से जवाब मिला–''श्री दिग्विजय सिंह जी, मैंने आपके द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं को नोट कर लिया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति वर्तमान में 'कारागार-स्थिति, अवसंरचना और सुधार' विषय की जाँच कर रही है, इसलिये आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिये खेद है।''

जब बीते महीनों में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं के पेपर लीक होने और उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ियों के कारण कई छात्रों ने अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया, देश की परीक्षा प्रणाली पर से लोगों का पूरा विश्वास उठ गया, तब दिग्विजय सिंह ने उस विश्वास को बहाल करने के लिये शिक्षा विभाग की स्थायी समिति के अध्यक्ष के नाते एक और बड़ी पहल की। परीक्षा घोटाला उजागर करने वाले छात्र सार्थक सिद्धान्त को समिति के सामने पेश किया गया और घोटाले कहाँ और कैसे होते हैं, यह राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर दिया। अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये और संसदीय समिति की रिपोर्ट अन्ततः संसद को सौंप दी।

उनके इन प्रयासों से बदलाव कितना आयेगा, यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो कुछ नहीं करते, बल्कि उनके ही नाम अवश्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखता है जो बदलाव और विश्वास बहाल करने की नींव रखते हैं। इतिहास आम के पौधे को रोपने वाले उसी व्यक्ति को याद रखता है जो उसे रोपते समय सिर्फ इसलिये खुश होता है कि भावी पीढ़ियाँ उस वृक्ष में लगने वाले मीठे आम को खाकर तृप्त होंगी।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व,भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कोठीबाजार बैतूल निवासी पिंकी साहू ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर 5 वर्ष तक का वेतन दिए जाने के आदेश हुए थे। किंतु अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। जिस पर कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण की जानकारी ली तथा तत्काल आवेदन निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज निराकरण नहीं होता है तो लापरवाही की स्थिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल और संकुल प्राचार्य बैतूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान अपर कलेक्टर वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में ग्राम बघोली निवासी उषा माकोड़े ने अवैध रूप से नाली निर्माण की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने बैतूल जनपद पंचायत सीईओ को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। तीवरखेड़ा निवासी सहदेव ने खेत में रिटेनिंगवॉल बनाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने प्रभात पट्टन जनपद सीईओ को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल निवासी गीतांजलि नरवरे द्वारा छात्रवृत्ति न मिलने एवं महाविद्यालय में रही परेशानियों के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।

सीमांकन करने के लिए निर्देश– जनसुनवाई में बडोरा निवासी सकून बाई मौखेड़े ने सीमांकन नहीं किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार बैतूल 2 को सीमांकन कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा भगवत राव ने भूमि का सीमांकन करवाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने आठनेर तहसीलदार को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। चोरडोंगरी निवासी रामनाथ द्वारा आने-जाने के लिए रास्ता संबंधी शिकायत पर अपर कलेक्टर ने सारणी तहसीलदार को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। भीमपुर तहसील के चुनालोमा निवासी दलसिंह ने अवैध कब्जा की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने भीमपुर तहसीलदार को जांच कर शीघ्र प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

पेयजल समस्या का निराकरण करने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में आमला तहसील के ग्राम बड़गांव निवासी ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से पीने के पानी की समस्या के निराकरण के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने आमला जनपद सीईओ को जांच कर पेयजल समस्या का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। बरसाली के ग्रामीणों द्वारा शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर नाला बंद किए जाने के संबंध में शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने बैतूल तहसीलदार को जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम नांदू निवासी ममता बाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के आवेदन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ का बड़ा ऐक्शन

चम्बल अभ्यारण्य में अवैध खनन से जुड़े 19 आरोपी एक वर्ष के लिए जिलाबदर

भोपाल/मुरैना । राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में पूर्व में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने सख्त कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय से जुड़े विभिन्न प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। उनके कृत्यों से न केवल लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी, बल्कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के पर्यावरणीय संतुलन एवं जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलाबदर आदेश जारी किए गए हैं।

जिलाबदर किए गए व्यक्तियों में रामनिवास पुत्र हरिकंठ गुर्जर निवासी जैतपुर, रनवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, डरूआ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, साहब सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, सुल्तान पुत्र सोवरन गुर्जर निवासी जैतपुर, केशव पुत्र बलवीर सिंह निवासी नायकपुरा, भरत पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी पिपरई, बालिस्टर पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी कैमरा, धारा सिंह पुत्र गोधन सिंह गुर्जर निवासी कैथरी, माखन पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी कैमरा, टाइगर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, भवूती पुत्र हाकिम गुर्जर निवासी जैतपुर, चीकू पुत्र संतोष गुर्जर निवासी बंधा, ऑफिसर पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर निवासी बंधा, शेरा उर्फ जबरा पुत्र सरूपा उर्फ रामस्वरूप गुर्जर निवासी पचोखरा, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बंधा, बादशाह पुत्र रमेश गुर्जर निवासी पचोखरा, ओमवीर पुत्र रामहेत गुर्जर निवासी हेतमपुर तथा नागेन्द्र पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी कैमरा शामिल हैं।

जारी आदेश के अनुसार उक्त सभी आरोपियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना सहित ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश अवधि के दौरान वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

विधायक कार्यालय में डॉ. मुखर्जी के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

सोहागपुर। सोहागपुर विधायक विजयपालसिंह के कार्यालय में ब्लाक भारतीय जनता पार्टी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रवाद, एकात्मता एवं जनसेवा का प्रतीक है। उनका बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। इस अवसर पर

नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, नगर पंचायत परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, पार्षद आशीष विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री ऋषभ गढ़वाल एवं घनश्याम रघुवंशी सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आने वाली पीढ़ियां गुनगुनाएंगी जन परिषद के गीत : दीपक वोहरा

भोपाल। जन परिषद के 37वें वार्षिक एवं सम्मान समारोह का आयोजन रवीन्द्र भवन, भोपाल में अत्यंत गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में भारत के पूर्व राजदूत एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अग्रणी ज्ञाता श्री दीपक वोहरा एसीएस,श्री अनुपम राजन तथा एयर मार्शल श्री प्रमोद श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान भी किया गया।

अपने प्रेरक उद्बोधन में पूर्व राजदूत श्री दीपक वोहरा ने कहा कि जन परिषद की 37 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उसके सेवा कार्यों तथा राष्ट्रीय एवंअंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पहचान को देखते हुए यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियां जन परिषद के रचनात्मक गीतों कोगुनगुनाएंगी। उन्होंने कहा कि आज विश्व अनेक चुनौतियों और अस्थिरताओं के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में जन परिषद जैसी संस्थाएं समाज कोसकारात्मक दिशा प्रदान कर रही हैं। श्री वोहरा ने कहा कि वे इन दिनों अत्यंत व्यस्त थे और भोपाल आने की स्थिति में भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जन परिषद के इतिहास, उपलब्धियोंऔर कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा भोपाल के अपने मित्रों से संस्था के संबंध में चर्चा की।

शराब दुकान में नकबजनी करने वाले चोर को सिलारी थाना माखननगर से किया गिरफ्तार

सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक राजन, एसडीओ पुलिसश्री संजू चौहान के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी के निर्देशन में विगत एक माह पूर्व शराब दुकान में नकबजनी कर दुकान से नगदी रुपये चोरी करने वाले आरोपी उमेश उर्फ कालू बहेलिया पिता जरसन बहेलिया उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिलारी चौराहिट थाना माखननगर को गिरफ्तार करके आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस ने बताया दिनांक 17 मई2026 को फरियादी राजेन्द्र मिश्रा पिता देवपाल मिश्रा, सेल्समेन शराब दुकान सोहागपुर ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनाँक 16. 17 मई की दरम्यानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने शराब दुकान में टीन शेड का स्क्रू खोलकर दुकान के अंदर घुसकर शराब दुकान के केस काउंटर मे रखे लगभग 25 हजार रुपये चोरी कर लिए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 315/2026 धारा 331(4),305 (आ) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना की जिसमें घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही फुटेज चैक किए गए। आरोपी की तलाश हेतु तकनीकी साधनों की मदद ली गई। जिसमें आरोपी की तलाश की गई ।

वन विभाग की बड़ी कार्यवाही , दुर्लभ 'रेड सेंड बोआ' जब्त, वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार

धार। जिले में वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध वन विभाग द्वारा बड़ी एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीव रेड सेंड बोआ को सुरक्षित जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई गई है।

यह कार्यवाही विजयानंथम टीआर, वन मंडल अधिकारी एवं सुनील सुलया, उप वन मंडल अधिकारी सरदारपुर के मार्गदर्शन तथा डॉ. शैलेंद्र सोलंकी, वन परिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। टीम में मनीषपाल राठौड़, प्रताप गोयल, पत्तल सिंह भारती, अर्जुन राठौड़ एवं रफीक खान शामिल रहे।

प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर बदनावर के कानवन क्षेत्र के समीप ग्राम दुधवाल निवासी कमल पिता विक्रम देवड़ा को हिरासत में लिया। वन परिक्षेत्र कार्यालय में पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने पकड़े गए रेड सेंड बोआ को बड़नगर (उज्जैन) स्थित एक रिश्तेदार के घर पर भूसे के ढेर में मटके के अंदर छिपाकर रखा है। सूचना के आधार पर टीम ने तत्काल दबिश देकर वन्यजीव को सुरक्षित बरामद कर जब्त किया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कमल देवड़ा के विरुद्ध वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 (संशोधन अधिनियम 2022) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी पर अधिनियम की धारा 9, धारा 39, धारा 44, धारा 48 एवं धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत वन्यजीवों का शिकार, अवैध कब्जा, परिवहन एवं व्यापार प्रतिबंधित है तथा दोषी पाए जाने पर कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

वन विभाग के अनुसार रेड सेंड बोआ संरक्षित श्रेणी का वन्यजीव है, जिसकी तस्करी गंभीर एवं गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आती है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की पूछताछ हेतु रिमांड पर लिया गया है।

निर्धारित समयावधि में 6 लाख 11 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मिले नये बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु सरल और सुविधाजनक तरीके से त्वरित नवीन बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में घर बैठे ही नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विगत जुलाई 2023 से शुरू किये गये ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से अब तक भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण वृत्त में 01 लाख 21 हजार 619 नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में 06 लाख 11 हजार से अधिक नए कनेक्शन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदान किये गए हैं। इनमें 10 किलोवॉट तक के अस्थायी कनेक्शन भी शामिल हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में तत्काल नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। नये कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के पोर्टल अथवा PAY एप पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदक द्वारा विधिवत ऑनलाइन आवेदन और भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत बिजली कंपनी द्वारा सर्वे एवं अन्य औपचारिकताएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर उपभोक्ता के परिसर में नया कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अमझेरा के शर्मा परिवार ने मां को दी अनोखी श्रद्धांजलि: 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत सौंपे 5 हजार पौधे

माँ कमलादेवी शर्मा की याद अब पेड़ों में जिएगी, दुख की घड़ी को संकल्प में बदला

धार। अमझेरा में शर्मा परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल को धरातल पर उतारकर मिसाल पेश की है। माताजी कमलादेवी शर्मा के निधन पर पुत्रों अश्विन शर्मा, अरुण शर्मा और अविनाश शर्मा ने दुख की घड़ी को पर्यावरण संरक्षण के संकल्प में बदल दिया। तेहरवीं के अवसर पर परिवार ने 1 लाख रुपए मूल्य के 5 हजार पौधे जिला प्रशासन को भेंट किए। इन पौधों को जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाकर संरक्षित किया जाएगा। शर्मा परिवार की इस पहल की ग्राम अमझेरा सहित पूरे जिले में चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि श्रद्धांजलि देने का यह अनोखा तरीका समाज के लिए प्रेरणा बनेगा।

इन पौधों के रूप में मां की याद हमेशा यादगार बनी रहेगी– इस मौके पर अश्विन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल से

प्रेरणा लेकर हमने मां की स्मृति में 5 हजार पौधे जिला प्रशासन को सौंपे हैं। इन पौधों के रूप में मां की याद हमेशा यादगार बनी रहेगी। हम समाज के अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि वे ऐसी पहल करें ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि मिले।'

वन विभाग ने ली सुरक्षा की जिम्मेदारी– तेहरवीं कार्यक्रम में जिला वनमंडलाधिकारी विजयानंथम टी आर विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने शर्मा परिवार की इस अनुकरणीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि ÷यह कार्य पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक है। वन विभाग इन 5 हजार पौधों को बड़ा करने और उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है। कमलादेवी शर्मा अब इन वृक्षों के रूप में धार की हरियाली बढ़ाएंगी।

क्या है 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह पहल लोगों से आग्रह करती है कि वे अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृभूमि और मातृशक्ति के सम्मान को जोड़ना है।

इस अवसर पर सरदारपुर से वन विभाग अधिकारी शेलेन्द्र सोलंकी, जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री,धार से समाजसेवी अशोक जैन, भाजपा के जिला मंत्री कमल यादव, धार प्रेस क्लब अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्रिपाठी , वरिष्ठ पत्रकार सुनील सचान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने प्रभावी कदम उठाएं: कलेक्टर विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने किए जा रहे कार्यो और गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा एसपी श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा गत बैठक के पालन प्रतिवेदन अनुसार संबंधित अधिकारियों से अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा एसपी श्री गुप्ता ने जिले में ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए दुर्घटना संभावित स्थलों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में स्कूल, कॉलेज चिकित्सालय सहित अन्य स्थलों के समीप सड़कों पर कैट आई, विभिन्न संकेतक चिन्ह या साइन बोर्ड, रैलिंग लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में स्कूल, कॉलजों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रकरणों पर चर्चा कर प्रभावितों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक नायक, यातायात प्रभारी लता मालवीय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। जिले में नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा जिले में नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मेडिकल दुकानों पर डॉक्टर के प्रिसक्रिपशन के बिना दवाओं या सीरप का वितरण नहीं हो, यह भी सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार बंद पड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों आदि उद्योगिक इकाईयों का पुलिस और राजस्व अधिकरियों के साथ निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

नगद इनाम की घोषणा

विदिशा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के द्वारा थाना कोतवाली जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 112/2025 की विभिन्न धाराओ के फरार आरोपियों में इदरीश बेदी पुत्र नईम अख्तर निवासी मालवीय वार्ड नम्बर 16 व हनुमान नगर लोधीपुरा बुरहानपुर जिला बुरहानपुर तथा सिविल लाइन जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 303/2026 के फरार आरोपी हेमंत पुत्र स्व0 नारायण प्रसाद पचौरीनिवासी ए-21 बालाजी एवेन्यु थाना सिविल लाइन विदिशा की सूचना देने वालो को क्रमशः पांच-पांच हजार रूपए नगद राशि देने की उद्घोषणा की है।

योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से किया जाए: कलेक्टर विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों, खुला आश्रय गृह में लाभान्वित बालकों, स्पांसरशिप योजना अंतर्गत लाभान्वित बालकों और पीएम केयर अंतर्गत लाभान्वित बालकों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि बाल कल्याण समिति के समक्ष अप्रैल 2026 से जून 2026 तक प्राप्त 44 प्रकरणों में से 38 प्रकरण निराकृत हो गए हैं तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार जिले में एकमात्र खुला आश्रय गृह, अशासकीय संस्था सियावास समाज कल्याण समिति बेगमगंज में संचालित है। जिसमें 25 बालकों को अस्थायी आश्रय प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पांसरशिप योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में योजना के तहत 719 बालकों का चिन्हाकंन किया गया है। इन बालकों को शासन से प्राप्त बजट अनुसार प्रतिमाह चार हजार रू प्रति बालक राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार कोविड-19 अंतर्गत जिले में 19 बालकों को पांच हजार रू प्रति बालक के मान से राशि प्रदान की जाती है। पीएम केयर योजना अंतर्गत जिले में 02 बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का होगा शुभारंभ

सीहोर (निप्र)। जिले में 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जिले के 1,82,084 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रथम दिवस में सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि आगामी दो दिनों तक विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए कि गए हैं कि अभियान संबंधी सभी तैयारियां समयपूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं और पोलियो की खुराक से एक भी बच्चा न छूटे।

■ इछावर एवं भैरूंदा में जनकल्याण शिविर आयोजित

सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार : राजस्व मंत्री

सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति योजनाओं का लाभ पहुंचाना है : केंद्रीय कृषि मंत्री

सीहोर (निप्र)। इछावर एवं भैरूंदा में जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। इछावर में आयोजित शिविर में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा शामिल हुए। इस अवसर उन्होंने जन चौपाल आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिविर निरीक्षण कर हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर लगाकर नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसानों को इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने और मिट्टी में जिन तत्वों की कमी हो, उसी के अनुसार खाद का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर सड़कों के माध्यम से गांवों में विकास की धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि, इस योजना में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवास योजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और अब पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले में लगभग 21 हजार लोगों का सर्वे किया गया है। सरकार का प्रयास है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें योजना का लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।

इछावर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि उन्हें एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं और योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। जनकल्याण शिविर इसी सोच का परिणाम हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इछावर में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना मेवाड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, इछावर नगर परिषद अध्यक्ष श्री देवेंद्र वर्मा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेखा जगदीश पटेल, सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, श्री गौरव सन्नी महाजन, श्री पंकज गुप्ता, एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा, जनपद सीईओ श्रीमती रूषाली पोरष सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और नागरिक उपस्थित थे।

आत्मा परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक, जैविक खेती कार्यशाला का शुभारंभ

विदिशा (निप्र)। कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा में आत्मा परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक और जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू रघुवंशी अध्यक्ष जनपद पंचायत बासौदा, विशिष्ट अतिथियों श्रीमती गायत्री रघुवंशी जिला जनपद सदस्य, श्री गौरव परमार, श्री पंकज नायक, श्रीमती अंजलि यादव, पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत बासौदा द्वारा किया गया। कार्यशाला में कृषि विभाग के उप संचालक कृषि श्री सचिन जैन, कृषि वैज्ञानिकों एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिया।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. विनोद गर्ग, डॉ. प्रवीण जगा और डॉ. प्रीति चौहान ने किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण संरक्षण होता है तथा मानव, पशु-पक्षियों एवं अन्य जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों एवं विधियों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती नीतू रघुवंशी ने किसानों से अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। श्रीमती गायत्री रघुवंशी ने केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। श्रीमती अंजली यादव ने किसानों को जैविक खेती के साथ-साथ उद्यान की फैसले व पशुपालन को भी अपनाने की सलाह दी। साथ ही प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले कृषकों ने कार्यशाला में अपने अनुभव साझा किए कार्यक्रम में कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी और अधिक संख्या में प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जिलेभर में आयोजित हुए सामूहिक योग कार्यक्रम

स्वस्थ समाज का दिया संदेश

सीहोर (निप्र)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिलेभर में उत्साह एवं उमंग के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीहोर जनपद कार्यालय, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिला न्यायालय, आरएके कॉलेज, कन्या शिक्षा परिसर, महिला आईटीआई, डाइट, नगर परिषद रेहटी, जिला अस्पताल, वर्धमान प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइडेंट ग्रुप बुधनी सहित अनेक शासकीय एवं निजी संस्थानों में योगाभ्यास कर स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया।

सीहोर जनपद कार्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती नाबड़ी बाई, जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती नमिता बघेल, एपीओ श्री गुलाब अहिरवार सहित माय भारत एवं हिताय एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगासन एवं प्राणायाम किए तथा योग के महत्व को समझते हुए नियमित अभ्यास करने का संकल्प लिया। इसी प्रकार जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू सहित अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स तथा न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों ने योग को तनावमुक्त एवं स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसके नियमित अभ्यास पर बल दिया। जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थाओं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरएके कॉलेज, कन्या शिक्षा परिसर, महिला आईटीआई एवं डाइट में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। वहीं जिला अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने योग कर स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। रेहटी नगर परिषद, वर्धमान प्राइवेट लिमिटेड तथा ट्राइडेंट ग्रुप बुधनी में भी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए योग के महत्व को रेखांकित किया।

ब्रांड एंबेसडर सारिका घारू ने लोकसंगीत के जरिए युवाओं को किया जागरूक

रायसेन (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के तहत रायसेन जिले में रोचक गतिविधियों के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग के कमिश्नर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं सचिव के मार्गदर्शन में आयोग की ब्रांड एंबेसडर सारिका घारू ने पारंपरिक और आधुनिक तौर-तरीकों का संगम कर नागरिकों को मतदातासूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया से जोड़ा।

रायसेन कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में जिले की विभिन्न ग्रामपंचायतों के नागरिकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सारिका घारू ने नागरिकों का एक बड़ा भ्रम दूर करते हुए विशेष रूप से स्पष्ट किया कि यह करीब 6 महीने पहले हुए भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर यानी लोकसभा या विधानसभा वाली मतदाता सूची से अलग प्रक्रिया है। वर्तमान में आपके गांव की पंचायत और शहर के नगर निकाय के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसलिए, जिन नागरिकों का नाम विधानसभा सूची में है, उन्हें भी इस स्थानीय निकाय की सूची में अपना नाम दोबारा जरूर जांचना चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोकसंगीत रहा, जिसके माध्यम से स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया गया।

विकास पुस्तिका के प्रकाशन हेतु सभी विभागों से योजनाओं, उपलब्धियों एवं निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में जिले की विकास पुस्तिका के प्रकाशन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, विशेष अभियानों तथा निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि विकास पुस्तिका का प्रकाशन समयबद्ध रूप से किया जा सके। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि विकास पुस्तिका जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों का समग्र दस्तावेज होगी। इसके माध्यम से आमजन को शासन की योजनाओं और जिले की प्रगति की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित प्रमुख उपलब्धियों, नवाचारों, विशेष अभियानों, हितग्राही मूलक योजनाओं, अधोसंरचना विकास कार्यों तथा अन्य उल्लेखनीय गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण बुलेट पाइंट्स के रूप में तैयार कर उपलब्ध कराएं। साथ ही इन गतिविधियों एवं कार्यों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ भी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किए जाएं। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विकास पुस्तिका में केवल तथ्यात्मक एवं प्रमाणिक जानकारी ही सम्मिलित की जाएगी। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने आंकड़ों का सत्यापन कर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुस्तिका जिले के विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए भी उपयोगी संदर्भ दस्तावेज सिद्ध होगी। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे तथा उन्हें विकास पुस्तिका के प्रकाशन कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

पीएमएफएमई योजना से मिले 27 लाख के लोन से जयप्रकाश ने शुरू की दूध गंगा डेयरी

प्रत्येक माह लगभग 40 हजार की हो रही आमदनी, 20 लोगों को मिला रोजगार

बैतूल (निप्र)। नौकरी की तलाश में लंबे समय तक भटकने के बाद मुलताई तहसील के डहुआ पंखा निवासी श्री जयप्रकाश चिकाने ने हार नहीं मानी। मध्यप्रदेश शासन की पीएमएफएमई योजना का लाभ लेकर उन्होंने दूध गंगा डेयरी की स्थापना की और आज न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं, अपितु करीब 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दूध गंगा डेयरी संचालक जयप्रकाश चिकाने ने बताया कि योजना के तहत आवेदन करने के बाद उन्हें बैंक से 27 लाख रुपए का ऋण मिला, जिसमें 10 लाख रुपए का अनुदान शामिल है। इस राशि से उन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू किया। वर्तमान में उनकी डेयरी आसपास के 15 से 20 गांवों से प्रतिदिन करीब 4 हजार लीटर दूध का संग्रहण करती है।

उन्होंने बताया कि संग्रहित दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, खोवा और मिठाई जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय दुकानों में बेचा जाता है। इसके अलावा नर्मदापुरम की एक निजी कंपनी को भी दूध की आपूर्ति की जा रही है। जयप्रकाश का कहना है कि सभी खर्च निकालने के बाद उन्हें करीब 40 हजार रुपए प्रतिमाह की आय हो रही है।

डेयरी में काम कर रहे युवाओं को भी फायदा

डेयरी में कार्यरत देवेन्द्र पोटफोड़े पिछले तीन वर्षों से यहां काम कर रहे हैं। उन्हें प्रतिमाह 12 हजार रुपए मानदेय मिलता है। देवेन्द्र ने बताया कि डेयरी में काम करने का फायदा यह है कि नौकरी के साथ वे अपने खेत और घरेलू काम भी देख लेते हैं।

उन्होंने बताया कि वे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक डेयरी में काम करते हैं। बाकी समय खेती और अन्य कार्यों में लगा लेते हैं। उनका कहना है कि किसी निजी कंपनी में नौकरी करने पर पूरा समय देना पड़ता, जबकि यहां रोजगार के साथ खेती भी आसानी से हो जाती है। दूध गंगा डेयरी के संचालक जयप्रकाश चिकाने ने पीएमएफएमई योजना के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

मेडिकल कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन हुआ

विदिशा (निप्र)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में योग समिति के तत्वावधान में भव्य एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योग के महत्व को आत्मसात किया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को स्वस्थ, संतुलित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिगरलाइन फिटनेस सेंटर, विदिशा की प्रोप्राइटर श्रीमती अंजली पंडित, योग प्रशिक्षक एवं आयुर्वेद-प्राकृतिक चिकित्सा

विशेषज्ञ श्री नीलेश विश्वकर्मा तथा विधान श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक एकाग्रता विकसित करने तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग एक प्रभावी साधन है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. मनीष निगम, योग प्रमुख डॉ. नरेंद्र पटेल सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में योग को समग्र स्वास्थ्य संवर्धन का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से योग करने तथा इसके संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया।कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं छात्र समन्वयन में डॉ. केशव बंसल, धनीराम दुबे, राशी विश्वकर्मा, वंशिका कौशिक, चेतन महाजन एवं राजा रघुवंशी की उल्लेखनीय भूमिका रही। योग समिति के सदस्यों तथा प्रतिभागियों के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर योग समिति द्वारा सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही सभी ने स्वस्थ, संतुलित एवं जागरूक समाज के निर्माण के लिए नियमित योगाभ्यास करने और योग के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक : मुख्यमंत्री

यूसीसी पर सभी जिलों में हो चुकी हैं बैठकें

प्रदेश में गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा 15 से 29 जुलाई तक

बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व को मिला 'इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवॉर्ड'

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहितालागू (यूसीसी) करने के लिएसभी जिलों में जन परामर्श बैठकें हो चुकी हैं। सभी जिलों में कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय परामर्श 22 जून को भोपाल में हुआ। इसमें सभी आयोगों, विभागों, राजनैतिक दलों और धर्मगुरुओं से पृथक-पृथक बैठकें आयोजित कर मत लिया गया। लगभग 3.49 करोड़ एस.एम.एस यूसीसी के सुझाव आमंत्रित करने के लिए समग्र के हितग्राहियों को भेजें गए। नागरिकों के 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, 90 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है। विधेयक के प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह जानकारी दी।

गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा के अंतर्गत सभी स्कूलों में होंगी गतिविधियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा दिनांक 15 से 29 जुलाई तक मनाया जा रहा है। इस अवधि में सभी स्कूलों में अलग अलग शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और गतिविधियां होंगी। इसमें जनप्रतिनिधि, पालक एवं विषय विशेषज्ञ शामिल होगें। इसमें विद्यार्थियों के विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक दिवस की कार्य योजना बनाई है, इसमें भाषण, निबंध प्रतियोगिता, संस्कृत श्लोक प्रस्तुति, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण, कैरियर मार्गदर्शन इत्यादि विषय शामिल किए गए हैं। इस अवधि में सांदीपनि विद्यालयों में एक दिवसीय गुरू पूर्णिमा उत्सव होगा। इसके अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शिनी, नवाचार इत्यादि के कार्यक्रम किए जाएगें। कार्यक्रम में अभिभावक, जनप्रतिनिधिगण और नागरिकों की सहभागिता होगी।

बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व की देश-विदेश में विशेष पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रसिद्ध वन्य जीव पर्यटन स्थल बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवॉर्ड 2026 में एडिटर्स चॉइस अवार्ड- बेस्ट वाईल्ड लाईफ डेस्टिनेशन श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। गोवा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, देश-विदेश के पर्यटकों के बीच अपनी समृद्ध जैव-विविधता, बाघों की अच्छी संख्या, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रभावी संरक्षण प्रबंधन के लिए विशेष पहचान रखता है। यह अवार्ड प्रदेश सरकार की जैव विविधता के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में पंचायत स्तर तक होंगी गतिविधियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 19 मार्च से प्रारंभजल गंगा संवर्धन अभियान का 25 से 30 जून 2026 की अवधि में समारोहपूर्वक समापन होगा। भारत सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में मध्यप्रदेश का तीसरा स्थान है। डिण्डौरी, खण्डवा तथा शहडोल देश के प्रथम 10 जिलों में तथा खण्डवा और इंदौर के नगरीय निकाय, देश के प्रथम 10 नगरीय निकायों में शामिल है। प्रदेश में अभियान में जल संरक्षण एवं संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में समारोहपूर्वक समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रदर्शनी, भाषण, ग्राम पंचायत में जनभागिता से किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन किया जाए और जल के सदुपयोग की शपथ भी दिलाई जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का किसान सम्मान निधि के लिए माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के प्रदेश भ्रमण संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 20 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित की गई। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 1640 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार माना।

मप्र में भाजपा कार्यसमिति की घोषणा

सीएम के बाद हैं शिवराज सिंह चौहान और चौथे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद बीजेपी कार्यसमिति की घोषणा हो गई है। कार्यसमिति में 106 सदस्यों को जगह मिली है। पहले नंबर सीएम मोहन यादव हैं और दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान को जगह मिली है। वहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौथे नंबर पर जगह मिली है। स्थाई आमंत्रित सदस्यों की सूची में 41 लोग हैं।

कार्यसमिति में इन लोगों को मिली है जगह

वहीं, बीजेपी कार्यसमिति में कुल 106 लोगों को जगह मिली है। पहले नंबर पर सीएम मोहन यादव हैं। शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, डीडी उइके, सावित्री ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विष्णु दत्त शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य, अरविंद सिंह भदौरिया, सम्पतियां उइके, कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंषाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाह, चेतन्य कुमार काश्यप, भूपेंद्र सिंह, कृष्णा गौर, संध्या राय और सांसद गणेश सिंह शामिल हैं।

ये भी हैं सदस्य

इसके अलावे हिमाद्रि सिंह, कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मिकी, माया नरोलिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह, हरिशंकर खटीक, कमल पटेल, गजेंद्र पटेल, रामेश्वर शर्मा, गिर्राज दंडोतिया, ओपीएस भदौरिया, विपिन गोस्वामी, रक्षा सिरोनिया, अभय चौधरी, इमरती देवी, वीरेंद्र जैन, नरेंद्र बिरथरे, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरिसिंह यादव, विनोद पंथी, ललिता यादव, ममता गुप्ता और गौरव तिवारी समेत ये नाम कार्यसमिति के सदस्य हैं।

फायर सेफ्टी के बगैर चलती कोचिंग सील, लखनऊ हादसे के बाद सख्ती

गीता भवन स्थित कैटालाइजर कोचिंग में नहीं मिले सुरक्षा इंतजाम

इंदौर। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर की कोचिंग क्लासों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में गीता भवन क्षेत्र स्थित कैटालाइजर कोचिंग क्लासेस पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया।

जांच के दौरान प्रशासनिक टीम को संस्थान में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं मिले। फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम घनश्याम धनगर अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर की अन्य कोचिंग संस्थाओं का भी चरणबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलेगी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं अभिभावकों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की पहल का स्वागत किया है।

---

17 आईएफएस के तबादले, रायसेन के प्रभारी डीएफओ हटे

हितेश खंडेलवाल रीवा से सिवनी, गुरलीन कौर सिवनी से छिंदवाड़ा पदस्थ

भोपाल (नप्र)। वन विभाग ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में कई जिलों के वन मंडल अधिकारियों (डीएफओ) को बदला गया है। तबादला सूची में वर्ष 2021 और 2022 बैच के आईएफएस अधिकारी भी शामिल हैं।

सबसे बड़ा बदलाव रायसेन जिले में किया गया है। यहां के प्रभारी वन मंडल अधिकारी मानसिंह मरावी को हटाकर पन्ना में पदस्थ अंशुल तिवारी को नया वन मंडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं मानसिंह मरावी को प्रशासनिक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।

शिवानी वन मुख्यालय पहुंचीं

वन विभाग द्वारा जारी आदेश में वन मंडल अधिकारी शिवानी को उपवन संरक्षक कार्यालय प्रधान वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल, प्रभंजन रेड्डी उपवन मंडल अधिकारी शिवपुरी को वन मंडल अधिकारी, अंशुल तिवारी वन मंडल अधिकारी विश्रामगंज उत्तर पन्ना को वन मंडल अधिकारी रायसेन, गुरलीन कौर उपवन मंडल अधिकारी कुरई दक्षिण सिवनी को वन मंडल अधिकारी छिंदवाड़ा, सुंदर निवेदन उप वन मंडल अधिकारी बैतूल को उपवन संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम (प्रतिनियुक्ति पर) पदस्थ किया गया है।

मेनका व्ही खंडवा से भोपाल आईं

मेनका व्ही उपवन मंडल अधिकारी खंडवा को वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी भोपाल, शैलेश माचरा उपवन मंडल अधिकारी उत्तर सागर को वन मंडल अधिकारी पर्यावरण वानिकी मंडल भोपाल, हितेश खंडेलवाल उपवन मंडल अधिकारी रीवा को वन मंडल अधिकारी सिवनी, विकास शर्मा उपवन मंडल अधिकारी नरसिंहपुर को वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी इंदौर, नीरज निश्चल उपवन मंडल अधिकारी गुना को उपवन संरक्षक वनबल प्रमुख कार्यालय पदस्थ किया गया है।

हिमांशु त्यागी विदिशा से झाबुआ पहुंचे

हिमांशु त्यागी उपवन मंडल अधिकारी विदिशा को वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी झाबुआ, प्रितेश मनोहर राव उपवन मंडल अधिकारी अनूपपुर को वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी रतलाम, विनोद जाखड़ उपवन मंडल अधिकारी जैतपुर शहडोल को उपवन संरक्षक राज्य वन विकास निगम भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर), अक्षत जैन उप मंडल उपवन मंडल अधिकारी पन्ना को वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी रीवा, समीर रंजन मिश्रा उपवन मंडल अधिकारी गौरवी सिंगरौली को वन मंडल अधिकारी दक्षिण बालाघाट, ध्रुव श्रीवास्तव उपवन मंडल अधिकारी चिचोली बैतूल को वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी बैतूल पदस्थ किया गया है। इसके अलावा प्रभारी वन मंडल अधिकारी रायसेन मानसिंह मरावी को प्रशासकीय आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख कार्यालय में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।

परोपकारी संस्थाओं के प्रोत्साहन से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का किया जाएगा सशक्तीकरण : शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में मध्यप्रदेश (परोपकारी संस्थाओं के लिए) मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद समिति ने विमर्श किया। बैठक में प्रस्तावित नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और समिति के सदस्यों ने नीति को जन-केंद्रित, सेवा-उन्मुख, गरीब एवं वंचित वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में मंत्रिपरिषद समिति के सदस्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह सहित अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री अशोक बर्णवाल, आयुक्त श्री धनराजू एस तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक एवं सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परोपकारी संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा-भाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आमजन तक पहुंचाना है।

वर्तमान में प्रदेश गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान मुख्यतः बड़े शहरों तक सीमित हैं, जिससे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के नागरिकों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य प्रदेश में उच्चस्तरीय तृतीयक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना, विशेषज्ञ एवं एमबीबीएस चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना, गरीब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना, अन्य राज्यों में उपचार हेतु मरीजों के पलायन को कम करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाना है।

डॉ. अशोक भार्गव विश्व हिंदी परिषद के कार्यकारी सदस्य मनोनीत हुए

नई दिल्ली। रीवा एवं शहडोल संभाग के पूर्व संभाग आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ अशोक कुमार भार्गव को विश्व हिन्दी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ विपिन कुमार द्वारा किया गया। विश्व हिंदी परिषद हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित संस्था है। इसका लक्ष्य हिंदी को विश्व भाषा के गौरवपूर्ण स्थान तक पहुँचाना है। डॉ विपिन कुमार ने डॉ. भार्गव के प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता, सांगठनिक कौशल एवं हिंदी के प्रति अटूट समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। इस अवसर पर विश्व हिन्दी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव डॉ विपिन कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ देवी प्रसाद मिश्रा एवं राष्ट्रीय संपर्क समन्वयक डॉ नंदकिशोर शाह सहित समस्त पदाधिकारियों ने डॉ भार्गव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉ भार्गव नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष, विश्व हिंदी परिषद के आजीवन सदस्य, लेखक, विचारक एवं ओजस्वी वक्ता हैं। उनका मानना है कि हिंदी हमारी अस्मिता की पहचान और भारत की आत्मा है। हिन्दी को विश्व भाषा बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा।

भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर ABVP: कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

कहा- एमएलबी गर्ल्स-कॉलेज के पास से शराब दुकान हटाएं

भोपाल (नप्र)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे तथा महारानी लक्ष्मीबाई (एमएलबी) गर्ल्स कॉलेज के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पोस्टरों पर शिक्षा के मंदिर के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी और जहां ज्ञान की ज्योति जलती है, वहां शराब की दुकान नहीं चलती जैसे संदेश लिखे थे। कुछ छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर भी विरोध जताते नजर आए। स्थिति को देखते हुए मौके पर 200 से अधिक पुलिसकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी और वॉटर कैनन तैनात किए गए थे।

प्रदर्शन के दौरान भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा छात्रों से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले में नियमानुसार जांच कर सात दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि सात दिन के भीतर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो आठवें दिन से फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

कलेक्टर बोले- 3 जून को नोटिस दिया था

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि पदभार संभालने के समय ही उन्हें इस शराब दुकान से जुड़े विवाद की जानकारी मिली थी। पूर्व में दिए गए ज्ञापन और शिकायतों के आधार पर 3 जून को संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से जिला स्तरीय समिति को सुनवाई कर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज से दुकान की दूरी सहित सभी नियमों और तथ्यों की जांच की जा रही है। समिति की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाएगा।

एबीवीपी नेता बोले- छात्राओं की सुरक्षा खतरे में

एबीवीपी के भोपाल महानगर सह मंत्री अमित महावर ने कहा कि एमएलबी गर्ल्स कॉलेज के पास शराब दुकान का संचालन छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण के लिए उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज के नजदीक शराब दुकान होने से छात्राओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

सीसीटीवी कैमरे लगाने ओवरब्रिज बनाने की भी मांग

प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर के सामने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि फ्लाईओवर के आसपास अकसर असामाजिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिससे छात्राओं को परेशानी होती है। परिषद ने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षित आवागमन के लिए ओवरब्रिज निर्माण और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित शराब दुकानों को हटाने की मांग की।